नई दिल्ली

मूल्य : 01 रुपए

पृष्ठ : 08

वर्ष : 14

अंक : 169

18 सितंबर, 2026 शुक्रवार

RNI No. DELMUL/2012/47011

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com

Email : timesofpedia@gmail.com

अंतर्राष्ट्रीय करियर समाप्त होने का अंदेश पहले ही हो गया था : भुवनेश्वर कुमार 07

संक्षिप्त वार्ता

पन्ना की हीरा खदान में मिला 27.29 कैरेट का हीरा

पन्ना। मध्यप्रदेश की पहचान बन चुकी पन्ना की हीरा नगरी ने एक बार फिर देश-दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पन्ना खदान क्षेत्र में संचालित एनएमडीसी के डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट में 27.29 कैरेट गुणवत्ता वाला जेम श्रेणी का हीरा मिला है। इसे पन्ना के खनन इतिहास की बड़ी उपलब्धियों में शामिल किया जा रहा है।

एनएमडीसी के अनुसार, मार्च 2024 में खदान दोबारा शुरू होने के बाद यह अब तक मिला सबसे बड़ा जेम क्वालिटी हीरा है। इससे पहले जुलाई 2026 में इसी श्रेणी में 13.16 कैरेट का हीरा मिला था। नया हीरा नियमित खनन के दौरान किम्बरलाइट अयस्क के प्रसंस्करण में प्राप्त हुआ है।

विशेषज्ञों के मुताबिक जेम क्वालिटी के बड़े आकार वाले प्राकृतिक हीरे बेहद दुर्लभ होते हैं। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, इस हीरे की कीमत दो करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। हालांकि वास्तविक कीमत हीरे की गुणवत्ता, रंग, कट और नीलामी में मिलने वाली बोली पर निर्भर करेगी।

सुरक्षाबलों ने देर रात 2 आतंकियों को मार गिराया

जम्मू। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षाबलों द्वारा आतंकवादियों का सफाया जारी है। सुरक्षाबलों को बुधवार को बड़ी सफलता मिली, जब देर रात हुए एक ऑपरेशन में दो आतंकवादियों को मार गिराया गया। हालांकि, इनकी अब तक पहचान नहीं हो सकी है। इससे पहले, कश्मीर के बडगाम में लश्कर के एक कमांडर को भी ढेर किया गया था।

ऊधमपुर जिले में बुधवार देर रात सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। लंबे समय तक चली गोलीबारी में दो आतंकी ढेर हो गए। सुरक्षाबलों को सोहन इलाके में तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों की जानकारी मिली थी। सूत्रों के अनुसार, मजालता के जंगलों में संदिग्ध हलचल महसूस होने पर सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गोलीबारी की। इसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया और संदिग्धों की तलाश में सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया।

पीएम मोदी ने कई बार किया यूपीआई से पेमेंट

नई दिल्ली। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन के साथ ही देश में एक बार फिर यूपीआई ट्रांजेक्शन पर लगने वाले संभावित शुल्कों को लेकर चर्चा गर्म है। भारत में यूपीआई अब चाय के ठेले से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक, हर जगह आम भुगतान का जरिया बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी कई मौकों पर डिजिटल पेमेंट और यूपीआई की सुविधा को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करते रहे हैं।

ऐसा ही एक दिलचस्प वाकया जनवरी 2024 में सामने आया था, जब फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत दौरे पर आए थे। जयपुर में मैक्रों के साथ भ्रमण के दौरान, पीएम मोदी ने न सिर्फ उन्हें यूपीआई के बारे में विस्तार से समझाया, बल्कि खुद भी डिजिटल भुगतान करके दिखाया था।

भारत बन रहा सेमीकंडक्टर हब

दुनिया में पहुंचने लगी मेड इन इंडिया चिप

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के पांचवें संस्करण का उद्घाटन किया। 17 से 19 सितंबर तक चलने वाले इस आयोजन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के प्लांट्स से निकलने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स अब देश के साथ दुनिया के बाजारों तक पहुंचने लगी हैं। चिप्स की कमी का असर मोबाइल फोन, कार और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतों पर पड़ सकता है।

पीएम मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में क्षमता तैयार करने में दशकों लगते हैं। भारत ने चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, उपकरण निर्माण और टेस्टिंग जैसी क्षमताओं पर एक साथ काम किया है। उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा चरण शुरू किया गया है। पहले चरण की वैल्यू करीब 70,400 करोड़ रुपए थी, जबकि दूसरे चरण में 1.18 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है।

सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विस्तार के लिए कंपाउंड सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन फोटोनिक्स जैसी तकनीकों को इकोसिस्टम में शामिल करना जरूरी है। एआई डेटा सेंटर में बड़ी संख्या में हाई-परफॉर्मेंस प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर उद्योग के साथ ऊर्जा सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है।

600 से ज्यादा प्रदर्शक, 40 से अधिक देशों की भागीदारी

इस साल सेमीकॉन इंडिया की थीम ह्यसिलिकॉन से सिस्टम तकः इकोसिस्टम का निर्माणह्न है। इसमें 600 से ज्यादा प्रदर्शक शामिल हो रहे हैं, जिनमें करीब 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं। 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी में ह्यसैंड टू सिलिकॉन टू सिस्टम्सह्न के जरिए चिप निर्माण से लेकर तैयार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तक की पूरी प्रक्रिया प्रदर्शित की जाएगी। सरकार के मुताबिक भारत में अब तक 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इनमें पहले चरण में मंजूर तीन इकाइयों में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है। केंद्र ने सेमीकॉन 2.0 को भी मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर से जुड़े पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करना है।

पीएम मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2026 का किया उद्घाटन

उन्होंने वैश्विक कंपनियों से भारतीय स्टार्टअप्स, डिजाइन फर्मों और ओसीआई के स्वामित्व वाली संस्थाओं के साथ सहयोग करने की अपील की।

तैयार करने पर दिया जोर

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पॉलिसी, फंडिंग और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के स्तर पर जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने उद्योगों से भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाने और देश में चिप डिजाइन व बौद्धिक संपदा तैयार करने पर जोर दिया।

गाजा में इजराइली बमबारी में क्षतिग्रस्त इमारत गिरी, 11 बच्चों समेत 21 की मौत

गाजा। पश्चिमी गाजा शहर में एक रिहायशी इमारत गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। मृतकों में 11 बच्चे और 6 महिलाएं शामिल हैं। इस हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। रिपोर्ट में बताया कि अल-सादा नाम की छह मंजिला इमारत बुधवार तड़के ढह गई। यह इमारत इजराइली बमबारी में क्षतिग्रस्त हुई थी। यह इमारत निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी का मुख्यालय थी। इस इमारत में करीब 100 विस्थापित लोग रह रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक बचाव टीमों ने 16 घंटे तक चले अभियान के दौरान 45 लोगों को सुरक्षित निकाला और 21 शव बरामद किए। उन्होंने बताया कि 35 अन्य लोग खुद ही निकलने में सफल रहे। इमारत के मलबे के बाहर दर्जनों शोकाकुल परिजन जमा हो गए।

पीएम मोदी ने जन्मदिन पर अन्नपूर्णा योजना की किश्त की जारी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर गुरुवार को देशभर में सेवा-संकल्प अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना की किश्त जारी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों को लंबे समय तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा।

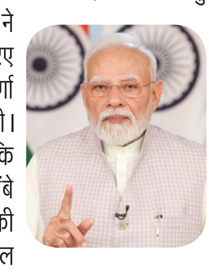

प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में राजनीतिक बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि 4 मई को राज्य के लोगों ने बदलाव का रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि इस बदलाव में बंगाल की माताओं और बहनों की भूमिका सबसे अहम रही है। प्रधानमंत्री के मुताबिक महिलाओं ने लंबे समय तक कई परेशानियां झेली हैं और विभिन्न सुविधाओं का इंतजार किया है। इसलिए नई सरकार की प्राथमिकता महिलाओं का जीवन आसान बनाना और उन्हें अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बताया। उन्होंने मोदी के जन्मस्थान गुजरात के वडनगर से वाराणसी के लिए करीब 1300 किलोमीटर लंबी बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी तरह वाराणसी से वडनगर के लिए भी बाइक रैली शुरू की गई।

इंडिगो का झटका

नवजात शिशु किराया 1000 रुपये महंगा

अहमदाबाद। इंडिगो ने अपने यात्रियों की जेब पर बोझ बढ़ाते हुए घरेलू उड़ानों के लिए किराए और अन्य सेवाओं के शुल्कों में बढ़ोतरी कर दी है। इंडिगो एयरलाइन ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों के किराए में सीधा 1,000 रुपये का इजाफा किया है। अब माता-पिता को अपनी गोद में बच्चे को बैठाकर यात्रा कराने के लिए 2,000 रुपये के बजाय 3,000 रुपये चुकाना होगा। इस फैसले से यात्रियों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि किराया बढ़ने के बावजूद इन बच्चों को उड़ान में कोई अलग सीट आवंटित नहीं होती। हालांकि, यात्रा के दौरान बुकिंग के समय शिशु की जानकारी देना अनिवार्य है।

इंडिगो को किराए बढ़ोतरी से सालाना भारी राजस्व मिलने का अनुमान है। देशभर में हर साल 10 लाख से अधिक नवजात शिशु अपने माता-पिता के साथ हवाई सफर करते हैं। प्रतिदिन करीब 1,850 घरेलू उड़ानों का संचालन करने वाली इंडिगो को किराए में की गई इस बढ़ोतरी से सालाना करीब 90 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है।

एयरलाइन ने सिर्फ शिशु किराया ही नहीं, बल्कि अतिरिक्त सामान और अन्य सेवाओं के चार्जेस में भी इजाफा किया है। घरेलू उड़ानों पर अतिरिक्त सामान की दर 700 प्रति किलो से बढ़ाकर 800 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है। इसका मतलब है कि अगर कोई यात्री तय सीमा से 5 किलो अतिरिक्त सामान ले जाता है,तब यात्री को अब 500 रुपये अधिक चुकाना होगा।

नैनीताल की 70 फीसदी पहाड़ियां अपनी जगह से खिसक रहीं

नैनीताल। उत्तराखंड के नैनीताल की पहाड़ियों को लेकर एक चौंकाने वाला शोध सामने आया है, जिसमें वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि शहर की 70 फीसदी से अधिक पहाड़ियां लगातार खिसक रही हैं।

इस भू-अस्थिरता को देखते हुए, वैज्ञानिकों को 1880 जैसी किसी बड़ी त्रासदी की पुनरावृत्ति का डर सता रहा है, जब एक विनाशकारी भूस्खलन ने बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान किया था। इन पहाड़ियों की मौजूदा स्थिति को गहराई से समझने के लिए, वैज्ञानिकों ने वर्ष 2017 से 2024 के बीच सेंटिनल-1ए सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण किया। शोध के दौरान यह पाया गया कि पहाड़ियों में होने वाली हलचल की औसत दर सालाना 10 से 19 मिलीमीटर रही, जिसमें वर्ष 2023 में यह गतिविधि सबसे अधिक दर्ज की गई।

नैनीताल में कुल 68.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किए गए इस विस्तृत शोध के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी बलियानाला क्षेत्र हर साल 5 से 11 मिलीमीटर की दर से नीचे धंस रहा है, जो चिंता का एक प्रमुख विषय है। इसके विपरीत, शेर-का-डांडा रिज में भूमि सालाना 10 से 20 मिलीमीटर (औसतन 12 मिलीमीटर से अधिक) की दर से ऊपर उठ रही है। यह असामान्य गतिविधि एक जटिल भूगर्भीय प्रक्रिया का संकेत है। यह महत्वपूर्ण शोध 10

सितंबर को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शोध जर्नल स्प्रिंगर नेचर के ह्यबुलेटिन ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी एंड द एनवायरनमेंटह्न में प्रकाशित हुआ है, जो इसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता को रेखांकित करता है। शोध में यूपीईएस देहरादून की अचला जोशी, डॉ. गिरीश चंद्र कोठियारी और अतुल के पाटीदार व अन्य विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है कि नैनीताल जैसे संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों की निरंतर और प्रभावी निगरानी की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने सुझाया कि उपग्रह-आधारित निगरानी प्रणाली का उपयोग करके धीरे-धीरे खिसक रही जमीन और संभावित भूस्खलन वाले क्षेत्रों की समय रहते पहचान की जा सकती है, जिससे संभावित आपदाओं को रोकने या उनके प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी।

खतरे को कई गुना बढ़ा सकती है

अध्ययन में 68.62 वर्ग किलोमीटर के पूरे क्षेत्र को भूस्खलन के खतरे के आधार पर तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। इसमें से 17.08 वर्ग किलोमीटर यानी 24.9 फीसदी क्षेत्र को उच्च जोखिम वाला पाया गया, जो कि तत्काल ध्यान देने की मांग करता है। वहीं, 40.87 वर्ग किलोमीटर यानी 59.6 फीसदी क्षेत्र मध्यम जोखिम वाली श्रेणी में रहा, जबकि 10.66 वर्ग किलोमीटर यानी 15.5 फीसदी क्षेत्र कम जोखिम वाली श्रेणी में शामिल किया गया। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में बलियानाला और नैनीताल झील भ्रंश का दक्षिण-पूर्वी हिस्सा प्रमुखता से शामिल हैं, जो शहर के लिए विशेष खतरा पैदा करते हैं। अध्ययन में भू-अस्थिरता को मेन बाउंड्री थ्रस्ट, नैनीताल झील भ्रंश, कृष्णनगर भ्रंश, मनोरा भ्रंश, रामगढ़ थ्रस्ट और ज्योल थ्रस्ट जैसी जटिल भूगर्भीय संरचनाओं से भी जोड़ा गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार, अत्यधिक बारिश, कमजोर ढलान और अनियंत्रित मानवीय गतिविधियां मिलकर भूस्खलन के खतरे को कई गुना बढ़ा सकती हैं।

राहुल ने बताया मोदी टैक्स, 5 सांसदों ने किया समर्थन

नई दिल्ली। यूपीआई लेनदेन पर नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को लेकर कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच विवाद गहराता जा रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नए एमडीआर फ्रेमवर्क को ह्यमोदी टैक्सह्न बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। हालांकि, इस राजनीतिक खींचतान के बीच संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की एक पुरानी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यूपीआई के लिए एक टिकाऊ राजस्व व्यवस्था की जरूरत पर बल दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस समिति में पांच कांग्रेसी सांसद भी शामिल थे, जिनमें पूर्व वित्त मंत्री पी.

चिदंबरम भी थे, और उन्होंने इस रिपोर्ट का समर्थन किया था।

वित्त संबंधी स्थायी समिति ने 12 अगस्त को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में यूपीआई के लिए टियर-आधारित एमडीआर या राजस्व व्यवस्था को बिना देरी अधिसूचित कर लागू करने की वकालत की थी। समिति में कांग्रेस के पी. चिदंबरम के अलावा मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, किशोरी लाल और के. गोपीनाथ शामिल थे। रिपोर्ट को बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली समिति ने सर्वसम्मति से अपनाया था और प्रकाशित कार्यवाही में किसी तरह की असहमति दर्ज नहीं की गई थी।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में यूपीआई के लिए राजस्व मॉडल की आवश्यकता को स्पष्ट किया था। उसने बताया कि 2026-27 के बजट में यूपीआई और रुपे पर जीरो-एमडीआर नीति से पैदा होने वाली लागत की भरपाई के लिए मात्र 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, यूपीआई के हर महीने 150 अरब तक लेनदेन करने और 60 करोड़ नए यूजर्स जोड़ने का अनुमान है, लेकिन सरकार की मौजूदा प्रोत्साहन राशि उद्योग की वास्तविक लागत का केवल 11 फीसदी और संभावित एमडीआर संग्रह का करीब 14 फीसदी ही कवर करती है।

हमें अमेरिकन पुलिस की तरह काम करना होगा: किरण बेदी

गुरुग्राम हिट-एंड-रन जैसे मामलों पर पूर्व आईपीएस की राय

नई दिल्ली। गुरुग्राम में हुए हालिया हिट-एंड-रन मामले पर अपनी राय रखते हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने कहा है कि ऐसे लोगों के मन में डर पैदा करना बेहद जरूरी है। उनका मानना है कि जब लोग गाड़ी चलाते समय लापरवाही या जानबूझकर ऐसी खतरनाक हरकतें करते हैं, तो उन्हें इसके गंभीर नतीजों से डरना चाहिए, जैसे गाड़ी और लाइसेंस छिन जाना, हथकड़ी लगना, जेल जाना, सजा भुगतना, भारी जुर्माना भरना और सबके सामने बेइज्जती होना। यह घटना साफ तौर पर दिखाती है कि आरोपी आदमी एक महिला को अपने साथ तेज रफ्तार में चलते हुए बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे यह बात पसंद नहीं आई कि एक महिला उसके साथ बराबरी कर रही है, और अपना दबदबा दिखाने के लिए उसने महिला का रास्ता काटा। अगर लड़की की मोटरसाइकिल पर कैमरा नहीं होता, तो शायद हमें इस घटना के बारे में कभी पता ही नहीं चलता।

किरण बेदी ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी हरकतें होती रही हैं और होती रहेंगी, जब तक कि हम डर को नहीं बढ़ाते। उन्होंने कहा कि इन लोगों में डर की कमी है, और हमें यह डर पैदा करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि डर पैदा कैसे करें? बेदी के अनुसार, हमें ऐसे लोगों को पकड़ने की संभावनाओं को बढ़ाना होगा, जिसका मतलब है कि अब हमें तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करना पड़ेगा। जैसे आजकल कैमरे हमें अपराधों को सुलझाने में मदद कर रहे हैं। अभी सामान्य अपराध के लिए ट्रैफिक पुलिस कैमरे का उपयोग कर रही है, नंबर नोट करती है और घर पर ई-चालान आ रहा है।

लोगों को डर हो रहा है कि कैमरा पकड़ लेगा। हाईवे पर स्पीड की समस्या है, हमें यहां भी कैमरे लगाने होंगे। किरण बेदी ने बताया कि अमेरिकन पुलिस यही करती है; उनके पास इंटरसेप्टर्स होते हैं जो पीछे से आते हैं और पता भी नहीं चलता। वे तुरंत हथकड़ी लगाते हैं ताकि अपराधी कोई हरकत न कर पाए। उसके बाद उसकी गाड़ी, उसकी चाबी, उसका लाइसेंस सब ले जाते हैं। फिर पूछते हैं कि अब बताओ, तुम कैसे कर रहे हो ये हरकत? उन्होंने कहा कि जब तक हम डर नहीं बढ़ाएंगे, ऐसी हरकतें होती रहेंगी। ये डरे हुए नहीं हैं, इसीलिए तो अपनी मनमर्जी करते हैं।

भारत फोर्ज और प्रैट एंड व्हिटनी कनाडा मिलकर बनाएंगे लंबी समय तक उड़ने वाले ड्रोन

नई दिल्ली। भारत की कंपनी और अमेरिका की प्रमुख रक्षा कंपनी ने घोषणा की कि वे भारत के ज्यादा ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम मानवरहित विमान के विकास में सहयोग करेंगे।

एक संयुक्त बयान में भारत फोर्ज और प्रैट एंड व्हिटनी कनाडा ने कहा कि वे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के एक कार्यक्रम के तहत डिजाइन और विकसित किए जा रहे एचएएलई मानवरहित विमान (यूएवी) में उन्नत टर्बोप्रॉप इंजन के इस्तेमाल की संभावनाओं का आकलन करेंगे। प्रैट एंड व्हिटनी अमेरिका स्थित आरटीएक्स एक उपक्रम है।

यह सहयोग सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत में स्वदेशी मानवरहित हवाई प्रणालियों के विकास के प्रयासों को बढ़ावा देगा। एचएएलई यूएवी जमीन और समुद्री क्षेत्रों में लंबे समय तक निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और टोह लेने के अभियान संचालित करने में सक्षम होते है। बयान में कहा गया है कि

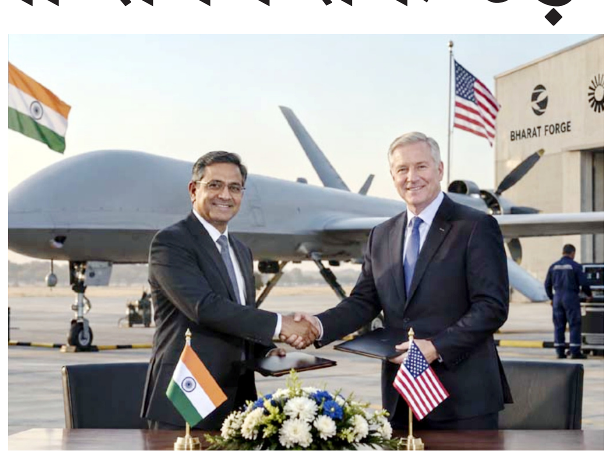

प्रैट एंड व्हिटनी कनाडा इंजन की अनुकूलता, प्रदर्शन और उसे विमान में लगाने से जुड़ी जरुरतों का आकलन करेगी।

भारत फोर्ज इंजन को विमान के ढांचे में जोड़ने का काम संभालेगी। इसमें इंजन की स्थापना की डिजाइन और विभिन्न प्रणालियों के बीच समन्वय से जुड़े काम शामिल होंगे। इस काम के लिए वह अपनी उन्नत इंजीनियरिंग, विनिर्माण और एयरोस्पेस प्रणालियों से जुड़ी क्षमताओं का इस्तेमाल करेगी। बयान में भारत फोर्ज लिमिटेड के उपाध्यक्ष और संयुक्त प्रबंध निदेशक के हवाले से कहा कि भारत फोर्ज का एयरोस्पेस कारोबार भारत की स्वदेशी एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रैट एंड व्हिटनी कनाडा के साथ सहयोग करने पर गर्व महसूस करता है।

उन्होंने कहा कि प्रैट एंड व्हिटनी की दुनिया भर में प्रमाणित प्रणोदन तकनीक को भारत फोर्ज की इंजीनियरिंग और प्रणालियों के एकीकरण से जुड़ी विशेषज्ञता के साथ मिलाकर हमारा लक्ष्य विश्वस्तरीय एचएएलई मंच के विकास में सहयोग करना है, जो भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता और रक्षा तैयारियों को मजबूत करेगा। प्रैट एंड व्हिटनी के उपाध्यक्ष और भारत प्रमुख ने कहा कि भारत फोर्ज के साथ यह सहयोग भारत की एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी महत्वाकांक्षाओं में सहयोग देने की कंपनी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

संपादकीय

यूपीआई मुफ्त नहीं

प्रधानमंत्री मोदी जो ढिंढोरा पीट रहे थे और देश की जनता को आश्वस्त कर रहे थे, उसका ढोल फट चुका है और सच सामने है। सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के जरिए ऐलान कराया है कि अब डिजिटल भुगतान (यूपीआई) मुफ्त नहीं होगा, बल्कि प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से आम ग्राहक, आम उपभोक्ता, आम आदमी की जेब कटेगी। अब यह यथार्थ भी सामने आ सकता है कि नकदी लेन-देन की ओर वापसी होने लगे! आम आदमी को यूपीआई लेन-देन की लत लग चुकी थी। उसे यह व्यवस्था आसान और सहज लगती थी। वह औसतन हर भुगतान यूपीआई के जरिए ही करने लगा था। फुटपाथ के पास रेहड़ी-पटरी, चायवाला अथवा टोकरी में फल बेचने वाली निरक्षर-सी महिला स्कैन के जरिए डिजिटल भुगतान स्वीकार करने लगे थे। इसकी लोकप्रियता, व्यापकता का पुख्ता प्रमाण यही है कि यूपीआई से साल भर में 314.23 लाख करोड़ रुपए का लेन-देन किया गया। यूपीआई इस्तेमाल करने वालों की संख्या 24,162 करोड़ बताई गई है। यूपीआई के जरिए रोजाना औसतन 66 करोड़ बार लेन-देन होता है। करीब 67 फीसदी भुगतान 2000 रुपए से अधिक का किया गया, बेशक सरकार ऐसा करने वालों की संख्या मात्र 4 फीसदी और 2000 रुपए से कम वाले 96 फीसदी बता रही है। दरअसल इन 4 फीसदी का मूल्य ही 67 फीसदी है। बेशक भारत सरकार की अधिसूचना में उल्लेख है कि व्यक्ति से व्यक्ति अथवा 2000 रुपए तक का लेन-देन करने वालों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। शुल्क वैसे भी दुकानदार, व्यापारी, यानी मर्चेन्ट को भरना होगा, लिहाजा इस शुल्क को एमडीआर का नाम दिया गया है। यह बड़ी हास्यास्पद और बेवकूफ बनाने वाली व्यवस्था है।

किराने, दूध-दही का दुकानदार या दवाओं की दुकान अथवा टीवी, फ्रिज, मोबाइल के शोरूम, अंतत:, यह हजार्ना क्यों भुगतेंगे? बैंक कितनी निगरानी रख सकते हैं? वे किसी को भुगतान की प्रणाली के लिए बाध्य नहीं कर सकते। एनपीसीआई ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 0.4 फीसदी और 75,000 रुपए या अधिक के बड़े लेन-देन के लिए अधिकतम शुल्क 300 रुपए तय किया है। आपको अब रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने और कृषि इनपुट सरीखे जरूरी भुगतान पर 5 रुपए (प्रति लेन-देन) शुल्क देना होगा। स्कूल-कॉलेज की फीस 2000 रुपए से अधिक की है, तो उस पर 300 रुपए की फ्लैट दर देनी होगी। आम आदमी पर बोझ कैसे नहीं पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी? संभव है कि डिजिटल भुगतान के मद्देनजर जितने लाखों करोड़ रुपए का लेन-देन हो रहा है, उससे टैक्स वसूलने का लालच सरकार ने महसूस किया होगा! यह सवाल भी सामने होगा कि यूपीआई के व्यापक, विविध नेटवर्क पर 20,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च क्यों किए जाएं? हर साल के बजट में 2000 करोड़ रुपए क्यों तय किए जाएं? क्यों न इसका कुछ बोझ और प्रभार देश की जनता के साथ साझा किया जाए? कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन अब मोदी सरकार का वैश्विक थाली बजाऊ प्रचार बेनकाब हो गया है। सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण भी नहीं आया है कि आखिर यह हजार्ना थोपने की नौबत क्यों आई? बेशक हमारा यूपीआई लेन-देन 11 अन्य देशों में भी प्रचलित है और 23 अन्य देशों के साथ समझौते विचाराधीन हैं। यह विदेश नीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन चिंता आम भारतीय की होनी चाहिए, जो बहुधा गरीब है, न्यूनतम आय वाला है और राजनीतिक दलों को वोट देकर सत्ता में पहुंचाते हैं। उन पर करों की बहुत मार है। बैंक से एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर फीस है। बैंक बैलेंस तय सीमा से कम है, तो चार्ज लगता है। चेकबुक का औसतन एक पन्ना 2-5 रुपए का है। चेक बाउंस होने पर 250-500 रुपए तक का जुमार्ना है। यदि बैंक खाता बंद कराना है, तो भी 200 रुपए फीस देनी पड़ती है। आम आदमी औसतन हर वस्तु और सेवा पर परोक्ष रूप से जीएसटी भी देता है। और ऐलानिया कृपा यह है कि आम आदमी पर एमडीआर नहीं लगेगी। न बैंक गरीब हैं और न ही एनपीसीआई घाटे में है। उसके खाते में करीब 1800 करोड़ रुपए का मुनाफा जमा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार को दे रखे हैं। आम आदमी को क्यों चूस रहे हो, सरकार जी? बहरहाल इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। भारतीय नागरिकों को मुफ्त में भुगतान करने की सुविधा जारी रहनी चाहिए। सरकार ने मुफ्त में भगतान की सुविधा देकर भारतीय नागरिकों को एक बड़ी सुविधा उपलब्ध करवाई थी, लेकिन अब इसमें फेरबदल करने से असंख्य भारतीयों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

ब्रिक्स से भारत को क्या लाभ

दिनांक 12 एवं 13 सितम्बर 2026 को ब्रिक्स का 18वां शिखर सम्मेलन दिल्ली के भारत मंडपम में सफलता पूर्वक सम्पन्न हो गया। ब्रिक्स का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग बढ़ाना है। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के साथ ही 10 अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री एवं उच्च स्तर के अधिकारी शामिल हुए। वर्ष 2025-26 के लिए भारत को ब्रिक्स का अध्यक्ष बनाया गया था, अत: भारत ने इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी एवं अध्यक्षता की। ब्रिक्स के माध्यम से विश्व की 11 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं एवं विकासशील देशों को एक मंच प्रदान किया जाता है। ब्रिक्स में शामिल देशों की कुल आबादी विश्व की कुल जनसंख्या का 49.5 प्रतिशत है और विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी है तथा वैश्विक व्यापार में 26 प्रतिशत की भागीदारी है। इससे वैश्विक स्तर पर ब्रिक्स का महत्व स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है। ब्रिक्स के सदस्य देश आपस में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय स्थिति, दूरसंचार, कृषि, श्रम, रोजगार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना, व्यापार और विश्व व्यापार संगठन सहित वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करते है। इस वर्ष के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम ह्लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माणह्व रखी गई थी। शिखर सम्मेलन में 45 पन्नों एवं 140 बिंदुओं के ह्लनई दिल्ली घोषणापत्रह्व को समस्त सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की यह सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि इस सम्मेलन में आपस में कुछ विरोधाभासी विचार रखने वाले देश (ईरान, साऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात) भी शामिल थे। ईरान के राष्ट्रपति एवं यूएई के राष्ट्रपति के बीच शिखर सम्मेलन के बीच आपस में वार्ता सम्पन्न हुई थी, जबकि दोनों देशों के बीच अमेरिका-ईरान युद्ध के संदर्भ में तनाव की स्थिति कायम है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रिक्स की स्थापना अमेरिका में हुई है। वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के मौके पर ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में ब्रिक को औपचारिक रूप दिया गया था। ब्रिक का पहिला उद्घाटन शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। वर्ष 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के साथ ब्रिक को ब्रिक्स में विस्तारित करने पर सहमति हुई थी। तदनुसार, दक्षिण अफ्रीका ने 2011 में सान्या में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जनवरी 2024 से और इंडोनेशिया जनवरी 2025 में ब्रिकस के पूर्ण सदस्य बने। इसके बाद बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम 2025 में भागीदार देशों के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने उदबोधन में उक्त ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कई आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विषयों की ओर समस्त सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति

डॉनल्ड ट्रम्प ने विभिन्न देशों से अमेरिका को होने वाले कई उत्पादों के निर्यात पर भारी भरकम टैरिफ लगाया था, इसी प्रकार चीन ने भी आवश्यक मिनरल के निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे, इस प्रकार की स्थित पुन: न बनें इस हेतु यह सुझाव दिया गया है कि तकनीकी एवं आवश्यक मिनेरल्स को विभिन्न देशों द्वारा हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसका सीधा सीधा विपरीत प्रभाव विकासशील देशों के विकास पर पड़ता है। जब हम वैश्विक स्तर पर एक परिवार की बात करते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों पर इस धरा पर निवासरत पूरी मानवजाति का समान अधिकार है। इसके उपयोग को कुछ देशों द्वारा रोका नहीं जाना चाहिए। भारतीय सनातन संस्कृति में तो प्रकृति को मां के समान माना जाता है, अत: प्रकृति का शोषण नहीं बल्कि आवश्यकता अनुसार दोहन होना चाहिए। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन भी आवश्यक है। विकास और पर्यावरण एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं केवल आवश्यता है कि दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया जाय। हाल ही के समय में महामारी, जलवायु आपदाओं एवं सप्लाई चैन में रुकावटों ने दिखाया है कि विभिन्न देश एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर है। एक देश में आया संकट दूसरे देश को भी प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रिक्स के सदस्य देशों को आपस में सहयोग बढ़ाने तथा सप्लाई चैन को मजबूती प्रदान करने की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच आपस में छोटे कारोबारों को बढ़ावा दिए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए और उन्हें नए बाजार और पर्याप्त वित्त की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के प्रयास भी होने चाहिए ताकि रोजगार के नए अवसर निर्मित हों और अंतिम पंक्ति पर खड़े नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके। इसके लिए ह्लब्रिक्स कनेक्टह्व के माध्यम से गरीब नागरिकों को काम के लिए आवश्यक कौशल सीखने, रोजगार के अवसर बढ़ाने एवं मातृशक्ति को अधिक काम के मौके देने का प्रयास किया जाना चाहिए। छोटे कारोबारियों को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से इफ्फ्ऊर टरटए पोर्टल प्रारम्भ किया गया है। इससे छोटे कारोबारी नए बाजारों से जुड़ सकेंगें। ब्रिक्स देशों में कार्य कर रहे स्टार्टअप्स को आपस में जोड़ने के लिए ब्रिक्स इनक्युबेटर नेट्वर्क बनाया जा सकता है। इसी प्रकार, नए और बड़े स्तर के नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड भी बनाया जा सकता है। ब्रिक्स देश आपस में कारोबार को सरल बनाने के उद्देश्य से स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ, अलग अलग देशों के ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। इससे एक देश के नागरिकों को दूसरे देश के नागरिकों को राशि भेजना बहुत आसान होगा और अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता कम होगी।

ब्रिक्स स्थापना से भारत को विशेष लाभ हुआ है। सामरिक दृष्टि से भारत का वैश्विक स्तर पर महत्व बढ़ा है। भारत आज न केवल ब्रिक्स बल्कि जी-20, जी-7, क्वाड, एससीओ जैसे वैश्विक संस्थानों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इससे वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ी है एवं अन्य देश आंज भारत की आवाज को गम्भीरता से सुन रहे हैं। विभिन्न देशों के नागरिक आज सनातन संस्कृति के संस्कारों को अपनाने हेतु लालायित हैं क्योंकि इस संदर्भ में भारत के व्यवहार से ये देश अत्यधिक प्रभावित हैं। साथ ही, भारत को कई प्रकार के आर्थिक लाभ भी होने जा रहे हैं और भारत में विदेशी निवेश बढ़ने की सम्भावना बनी है। ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों के बीच आपसी समझदारी बढ़ी है और इससे इन देशों के बीच आर्थिक साझेदारी भी बढ़ेगी। आतंकवाद के खिलाफ मजबूत संदेश गया है कि भारत किसी भी कीमत पर आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। नई दिल्ली घोषणापत्र में रूस एवं चीन सहित समस्त ब्रिक्स सदस्य देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा भी की है। इसमें यह भी कहा गया है कि आतंकियों को पनाह देने वालों के खिलाफ मिलकर कार्यवाही करनी चाहिए। साथ ही, आतंकियों तक पहुंचने वाली फंडिंग को रोकने और उन्हें सुरक्षित ठिकाने देने वालों पर भी कार्यवाही की जानी चाहिए।

भारत आज ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। इस क्षेत्र के देश भारत पर भरोसा करने लगे हैं। इससे भारतीय रुपए की वैश्विक स्तर पर साख बढ़ सकती है क्योंकि ब्रिक्स के सदस्य देश आपस में स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने के प्रयास कर रहे हैं। यूपीआई एवं रूपे कार्ड की स्वीकार्यता कई देशों में अब बढ़ रही है। आपस में स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने से भारतीय रुपए को मजबूती मिलेगी एवं इससे मंहगाई बढ़ने की गति कम होगी। ब्रिक्स ने वर्ष 2015 में डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) की स्थापना की थी। इस बैंक ने भारत को 10,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि का ऋण प्रदान किया है। इस ऋणराशि का उपयोग मुंबई मेट्रो लाइन डालने के लिया किया जा रहा है। इंदौर में मेट्रो भी इसी ऋण से बनी है। दिल्ली-गाजियाबाद क्षेत्रीय रेल्वे लाइन इसी ऋण से बिछाई गई है। कुल मिलाकर भारत में आधारभूत संरचना खड़ी करने में ब्रिक्स द्वारा स्थापित उक्त बैंक का महत्वपूर्ण योगदान है।

(लेखक-प्रहलाद सबनानी)

बैंकों की कमाई बढ़ी, बैंक के उपभोक्ताओं से लूट ?

भारत में बैंकिंग व्यवस्था पिछले एक दशक में तेजी से बदली है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को अधिकाधिक मजबूत बनाने, काले धन की अर्थव्यवस्था को, खत्म करने के लिए नकदी के बजाय बैंकिंग और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने तथा हर लेन-देन को वित्तीय व्यवस्था के दायरे में लाने पर जोर दिया है। इसका परिणाम यह हुआ, आम नागरिक की रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियां बैंक खाते से जुड़ गई। सवाल यह है कि जब ग्राहक बैंकिंग व्यवस्था पर सरकारी नियम कानून के कारण अधिक निर्भर हो गए हैं, ऐसी स्थिति में जब बैंकों की कमाई बढ़ रही है। डिजिटल लेनदेन होने के कारण कर्मचारियों की संख्या कम हो रही है। बैंकों का व्यापार बढ़ रहा है, कर्मचारी और अधिकारियों की संख्या बिजनेस और खाते की तुलना में कम हो रही है। तब बैंकिंग सिस्टम में उपभोक्ताओं से सर्विस के रूप में ज्यादा पैसा क्यों वसूला जा रहा है? बैंकों में न्यूनतम बैलेंस, एटीएम के लेनदेन पर शुल्क, चेकबुक, नकद जमा, निकासी पर शुल्क, एसएमएस शुल्क, कार्ड, पेनल्टी और कई अन्य सेवाओं के लिए तरह-तरह के शुल्क वसूल किए जा रहे हैं, जो कुछ वर्ष पहले नहीं लगते थे। बैंकों की आय हर साल बढ़ रही है। सरकार को बैंकों से भारी टैक्स मिल रहा है। बैंकों के नेट प्रॉफिट बढ़ाने के बाद भी उपभोक्ताओं पर शुल्क क्यों लगाई जा रहीं हैं? 2022-23 में बैंकों की शुद्ध आय 1.05 लाख करोड़, सकल आय 2.63 लाख करोड़, 2023-24 शुद्ध लाभ 1.41 लाख करोड़, सकल आय 3.50 लाख करोड़, 2024-25 शुद्ध आय 1.78 लाख करोड़, सकल आय 4.01 लाख करोड़ पर पहुंच गई। इस बीच बैंकों ने हजारों करोड़ों रुपए का औद्योगिक ऋण बट्टे खाते में डाला, जिससे बैंकों की बैलेंस शीट में सकल और शुद्ध आय में कमी आई, यदि उसको भी जोड़ दिया जाए तो बैंकों ने आम उपभोक्ताओं को कामधेनु गाय की तरह दुहा है।

सरकार के अनुसार 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अब तक का सर्वाधिक 1.78 लाख करोड़ रुपये शुद्ध लाभ कमाया. सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का संयुक्त शुद्ध लाभ 4.01 लाख करोड़ रुपए रहा। निजी क्षेत्र समेत अन्य बैंकों का संयुक्त लाभ करीब 2.23 लाख करोड़ की कमाई की है। यह सिर्फ बैंकों के मुनाफे की बात नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जमा राशि मार्च 2015 के 71.95 लाख करोड़ से बढ़कर सितंबर 2025 में 146.27 लाख करोड़ पर पहुंच गई है। अर्थात जनता की बचत और बैंकिंग व्यवस्था का आकार दोनों तेजी से बढ़े हैं। इस कारोबार में बैंकों की आय भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। पिछले एक दशक में भारतीय रिजर्व बैंक का सरप्लस भी केंद्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण आय का स्रोत बन गया है। आरबीआई ने 2023-24 में 2.11 लाख करोड़ का सरप्लस केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया है। 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट में भी आरबीआई के वित्तीय परिणामों में बड़ा उछाल दर्ज हुआ। केंद्र सरकार रिजर्व बैंक से हर साल डिविडेंड के रूप में भारी वसूली कर रही है। इसके पहले इतने बड़े स्तर पर कभी भी रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को राशि ट्रांसफर नहीं की थी। सवाल बैंकिंग व्यवस्था के मुनाफे के खिलाफ नहीं है। बैंक लाभ कमाएं, मजबूत हों, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बैंकिंग सिस्टम मजबूत होना जरूरी है। पिछले एक दशक में ऑनलाइन के नाम पर बैंकों से गरीब से गरीब आदमी जुड़ा है। सरकारी सहायता भी बैंकों से जुड़ गई है। बैंकिंग आज अमीरों और मध्यम वर्ग के लिए नहीं, गरीबों के लिए मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है। ऐसी स्थिति में जिस तरह से बैंक उपभोक्ताओं से सर्विस के नाम पर कई तरीके से वसूली कर रहे हैं, इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है। यही कारण है, छोटे खाताधारक पर बैंकों द्वारा बार-बार शुल्क लगाने की नीति पर पुनर्विचार होना चाहिए। जिस ग्राहक की छोटी बचत से बैंकिंग व्यवस्था का विशाल आधार तैयार होता है, उसके लिए मूलभूत बैंकिंग सेवाओं को शुल्क-मुक्त या अत्यंत कम लागत वाला होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

सरकार ने मोबाइल से भुगतान करने को बैंकिंग सुविधा का सबसे बड़ा आधार बताया था। यूपीआई के जरिए लेनदेन को सरकार ने प्रोत्साहित किया था। अब इसी यूपीआई के जरिए आम आदमियों को एक ऐसे शुल्क की ओर ढकेला जा रहा है। 2,000 रुपए से ऊपर यूपीआई भुगतान पर 15 सितंबर 2026 से सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके अनुसार अब यूपीआई से पेमेंट करने पर शुल्क देना पड़ेगा। यह कितना होगा, अभी इसे स्पष्ट नही किया है। 2,000 तक के यूपीआई और रूपे डेबिट कार्ड भुगतान पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क अभी नहीं लगाया है। 2,000 से ऊपर शुल्क की संभावना पर चर्चा शुरू है। आवश्यकता इस बात की है, रिजर्व बैंक और सरकार बैंकिंग शुल्क की पारदर्शी सीमा तय करें। न्यूनतम बैलेंस, बेसिक एटीएम सुविधा, डिजिटल भुगतान, खाते की अनिवार्य सेवाओं और छोटी नकद जरूरतों पर अत्यधिक शुल्क को नियंत्रित किया जाए। आम खाता धारकों को कामधेनु गाय की तरह दौहने की प्रवृत्ति बंद हो। पेनल्टी ब्याज और अन्य दंडात्मक शुल्क भी वास्तविक लागत और ग्राहक की क्षमता के अनुरूप तय किए जाएं। बैंकों का मजबूत होना अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। सरकार द्वारा जो लाखों करोड़ रुपए के ऋण माफ किए गए हैं, उसका बोझ ग्राहक पर डालना सामाजिक न्याय का मॉडल नहीं हो सकता है। यह मॉडल पूंजीवादी व्यवस्था में संभव है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह एक अन्याय है। महंगाई, रोजगार की चुनौती और घटती बचत दर के दौर में सरकार को सुनिश्चित करना होगा, डिजिटल और बैंकिंग अर्थ व्यवस्था का लाभ आम खाताधारक को मिले। सरकार और बैंकों ने बैंकिंग लेनदेन को अनिवार्य लूट का हिस्सा बनाकर करोड़ों रुपए की जो कमाई की जा रही है, वह ठीक नहीं है। इसका लाभ डिजिटल कंपनियों को बड़े पैमाने पर हो रहा है। विपक्षी दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। जो आगे चलकर सरकार के लिए राजनीतिक दृष्टि से भी हानिकारक होगा।

लेखक - सनत जैन

पहाड़ के पानी से हमें कितना लाभ मिलेगा ?

नदियां किसी भी प्रदेश के लिए मात्र जल का स्रोत नहीं होतीं, वे उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और सामाजिक जीवन की रीढ़ होती हैं। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में यह महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यहां की जलधाराएं देश की ऊर्जा एवं जल आवश्यकताओं में महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं। ऐसे में टौंस नदी पर प्रस्तावित किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना को केवल एक बांध या बिजली परियोजना के रूप में देखना पर्याप्त नहीं।

यह परियोजना हिमाचल के प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक हितों, पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के भविष्य से गहराई से जुड़ी हुई है। 15 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के बीच किशाऊ परियोजना को लेकर समझौता हुआ। वर्षों से विभिन्न कारणों से अटकी यह परियोजना अब आगे बढ़ने की स्थिति में है। वर्तमान योजना के अनुसार लगभग 15624 करोड़ रुपए की लागत से 422 मेगावाट क्षमता की परियोजना विकसित की जानी है। इसमें लगभग 1562 मिलियन घन मीटर जल भंडारण की व्यवस्था होगी। परियोजना से लगभग 97 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने तथा करीब 1476 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का अनुमान है। किशाऊ परियोजना से हिमाचल को मिलने वाला सबसे महत्त्वपूर्ण प्रत्यक्ष लाभ बिजली और उससे जुड़ा आर्थिक प्रतिफल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार परियोजना के चालू होने के बाद हिमाचल को लगभग 1200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।

हिमाचल को परियोजना से 211 मेगावाट बिजली का हिस्सा मिलने की बात कही गई है और इस हिस्से की लागत राज्य पर नहीं डालने की व्यवस्था की गई है। हिमाचल जैसे सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्य के लिए यह व्यवस्था विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। प्रदेश की नदियां लंबे समय से जल विद्युत उत्पादन का आधार रही हैं, परंतु बड़े बांधों और विद्युत परियोजनाओं में भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर भूमि, पर्यावरण और पुनर्वास की लागत भी सामने आती है। यदि किशाऊ परियोजना में हिमाचल को बिजली तथा उससे मिलने वाला आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, जबकि विद्युत घटक की बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी अन्य लाभार्थी राज्यों द्वारा वहन की जाती है, तो इससे राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव कम हो सकता है। किशाऊ परियोजना के पीछे वर्षों का अंतरराज्यीय संवाद है। हिमाचल और उत्तराखंड के बीच परियोजना के विकास के लिए 2015 में समझौता हुआ था तथा 2017 में किशाऊ कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया। परियोजना की क्षमता और डिजाइन में समय के साथ परिवर्तन हुए। पुराने परियोजना विवरणों में 660 मेगावाट क्षमता का प्रस्ताव था, जबकि वर्तमान समझौते में 422 मेगावाट क्षमता का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि किशाऊ का स्वरूप समय के साथ बदलता रहा है और इसके साथ लागत, लाभ तथा राज्यों की जिम्मेदारियों की व्यवस्था भी पुनर्गठित होती रही है। परियोजना को लेकर सबसे बड़ा विवाद यही रहा कि इसकी लागत का भार किस राज्य पर कितना पड़ेगा और पानी तथा बिजली का लाभ किस अनुपात में मिलेगा। जून 2026 में केंद्र सरकार की मध्यस्थता में हुई सहमति के अनुसार जल घटक की लगभग 90 प्रतिशत लागत केंद्र सरकार केंद्रीय सहायता के रूप में वहन करेगी, जबकि शेष लागत भागीदार राज्यों द्वारा साझा की जाएगी। इसी प्रक्रिया में हिमाचल के हिस्से के पानी को दिल्ली और राजस्थान को उपलब्ध कराने के बदले उसके विद्युत घटक की लागत को लाभार्थी राज्यों द्वारा वहन करने की व्यवस्था सामने आई। यह व्यवस्था हिमाचल के लिए इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि परियोजना का जल लाभ मुख्य रूप से नीचे स्थित राज्यों तक पहुंचेगा। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को सिंचाई तथा पेयजल के क्षेत्र में लाभ मिलने की संभावना है। दूसरी ओर बांध और जलाशय का प्रत्यक्ष प्रभाव हिमाचल तथा उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों पर पड़ेगा। इसलिए हिमाचल के लिए अपने संसाधनों के बदले उचित आर्थिक प्रतिफल सुनिश्चित करना स्वाभाविक आवश्यकता रही है।

किशाऊ परियोजना का महत्त्व केवल लगभग 1200 करोड़ रुपए के संभावित वार्षिक आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है। यदि राज्य को नियमित रूप से बिजली का आर्थिक लाभ मिलता है, तो यह आने वाले वर्षों में हिमाचल की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में योगदान दे सकता है। जलविद्युत क्षेत्र में पहले से मौजूद राज्य की भूमिका को देखते हुए ऐसी व्यवस्था प्रदेश के लिए दीर्घकालीन राजस्व का एक अतिरिक्त माध्यम बन सकती है। तथापि 1200 करोड़ रुपए को निश्चित तत्काल राजस्व के बजाय परियोजना के संचालन के बाद मिलने वाला अनुमानित आर्थिक लाभ समझना अधिक उचित होगा। इस पूरी तस्वीर का दूसरा पक्ष सामाजिक प्रभाव है। पुराने परियोजना विवरणों के अनुसार हिमाचल में लगभग 1498 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होने तथा आठ गांवों और करीब 2092 लोगों के प्रभावित होने का अनुमान लगाया गया था।

वर्तमान परियोजना के अंतिम डिजाइन और पुनर्वास दस्तावेजों के अनुसार इन आंकड़ों में बदलाव संभव है, परंतु इससे यह स्पष्ट है कि परियोजना का प्रभाव केवल नदी और बिजलीघर तक सीमित नहीं रहेगा। विस्थापन किसी भी बड़ी परियोजना का सबसे संवेदनशील पक्ष होता है। भूमि का आर्थिक मुआवजा आवश्यक है, किंतु पर्याप्त नहीं। किसी परिवार की भूमि चली जाने का अर्थ उसकी आजीविका, सामाजिक संबंधों और जीवन-पद्धति में बदलाव भी होता है। इसलिए किशाऊ से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को केवल मुआवजे की प्रक्रिया न मानकर दीर्घकालीन सामाजिक पुनर्स्थापन के रूप में देखा जाना चाहिए। बेहतर आवास, आजीविका, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर पुनर्वास पैकेज का अभिन्न अंग होने चाहिए। पर्यावरण का प्रश्न भी इससे अलग नहीं किया जा सकता। बहरहाल, वास्तविक सफलता तब होगी जब परियोजना से देश की जल और ऊर्जा जरूरतें पूरी होने के साथ हिमाचल को उसके प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रतिफल मिलेगा।

सिकंदर बंसल
शिक्षाविद

आलेख

बुजुर्गों की देखभाल अहसान नहीं कानूनी बाध्यता है

आज के बदलते समाज की एक कड़वी और चिंताजनक सच्चाई बन चुकी है। आधुनिकता, एकल परिवार की चाहत और भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बच्चे अपने जन्मदाताओं को ही बोझ समझने लगे हैं। ऐसे में बुजुर्गों को न केवल मानसिक रूप से अकेलापन झेलना पड़ता है, बल्कि कई बार वे बुनियादी जरूरतों भोजन, स्वास्थ्य के लिए भी मोहताज हो जाते हैं

आजकल अनेक संतानें शादी के बाद अपने माता-पिता की ओर से आंखें फेर लेती हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य किसी न किसी तरह उनकी सम्पत्ति पर कब्जा करना ही रह जाता है जिस कारण अनेक बुजुर्ग अपनी ही संतानों के हाथों अपमान और अत्याचारों का शिकार हो रहे हैं।

भारत सरकार और देश की न्यायपालिका ने बुजुर्गों के संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाए हैं :माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण अधिनियम, 2007 : इस कानून के तहत यदि संतानें माता-पिता की देखभाल नहीं करती हैं, तो बुजुर्ग अपने क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय में शिकायत कर गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। संपत्ति वापसी का नियम (धारा 23): सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न अदालतों के फैसलों के अनुसार, यदि किसी बुजुर्ग ने इस शर्त पर अपनी संपत्ति संतानों के नाम की थी कि वे बुढ़ापे में उनकी सेवा करेंगे, और बाद में बच्चे मुकर जाते हैं, तो बुजुर्ग अपनी गिफ्ट डीड या संपत्ति हस्तांतरण को निरस्त करवाकर संपत्ति वापस ले सकते हैं।घर से बेदखली : अगर बच्चे अपने माता-पिता के ही घर में रहकर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या सेवा नहीं करते, तो कोर्ट उन्हें घर से बाहर निकालने का आदेश दे सकता है।

आपको बता दें इसीलिए माता-पिता अपनी सम्पत्ति की वसीयत तो अपने बच्चों के नाम अवश्य कर दें परंतु इसे ट्रांसफर न करें। ऐसा करके वे अपने जीवन की संध्या में आने वाली कई परेशानियों से बच सकते हैं।

भारत में वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण कल्याण अधिनियम, 2007के अंतर्गत स्पष्ट कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल करके संतानों द्वारा अपने कर्त्तव्य का पालन न करने, प्रताड़ित करने या संपत्ति हड़पने का प्रयास करने पर बुजुर्ग अपनी संतानों को दी हुई सम्पत्ति उनसे वापस लेने के लिए उन्हें कानूनन बाध्य कर सकते हैं। न्याय पालिका द्वारा इस साल कई ऐसे ही फैसले दिए गए जिनमे साफ कहा गया है कि अपने

बुजुर्गों की देखभाल भरण-पोषण सेवा संतानो का फर्ज ही नहीं है बल्कि कानूनन बाध्यता भी है आपको ऐसे अदालती फैसलों की सिलसिलेवार जानकारी बता रहे हैं बीती 2 फरवरी को कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस सूरज गोविंदराज ने अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल न करने वाले एक दम्पति को ट्रांसफर की गई संपत्ति का मालिकाना हक उनके बुजुर्गों को वापस दिलवाया।

6 फरवरी को झारखंड हाई कोर्ट ने बेटे और बहू द्वारा उत्पीड़ित लखन लाल पोद्दार और उनकी पत्नी उमा रानी पोद्दार की याचिका पर सुनवाई के दौरान एस. डी. एम. द्वारा पारित आदेश को बहाल रख कर पीड़ित दम्पति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनके बेटे और बहू को तुरंत अपने माता-पिता का जबरन कब्जाया मकान खाली करने का आदेश दिया। 2 मई को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार ने बुजुर्गों को भरण-पोषण कल्याण अधिनियम के अंतर्गत अपने सास-ससुर को प्रताड़ित करने वाली एक महिला को अपने सास-ससुर के घर से निकाल बाहर करने का मैंटेनेंस ट्रिब्यूनल द्वारा सुनाया गया फैसला सही ठहराया ताकि महिला के बुजुर्ग सास-ससुर वहां शांति से रह सकें।

9 मई को गदरपुर (उत्तराखंड) में माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिकरण न्यायालय ने अपने बेटे व बहू के अत्याचारों के शिकार बुजुर्ग दम्पति, जिन्हें अपने ही घर में सम्मानपूर्वक जीवन जीने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, के बेटे और बहू को उनकी संपत्ति से बेदखल करने के आदेश जारी किए।

4 जुलाई को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने 93 वर्षीय बुजुर्ग महिला संतोष खन्ना की शिकायत पर उनके बड़े बेटे देवेंद्र और बहू नीरजा को तुरंत उनका घर खाली करने का आदेश दिया। महिला ने अपने बेटे व बहू पर लगातार उन्हें प्रताड़ित करने और उनसे अपने जीवन को खतरे के दृष्टिगत दोनों को घर से निकालने की गुहार लगाई थी।

20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराध्य ने लखनऊ की एक 81 वर्षीय बुजुर्ग महिला को वृद्धाश्रम जाने के लिए मजबूर करने वाले उसके पोते और बहू को तुरंत उनके घर से निकाल बाहर करने का आदेश दिया।

28 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे के एक फ्लैट से बेटे को तुरंत बेदखल करने के एडिशनल कलैक्टर (ट्रिब्यूनल) के आदेश को सही करार देते हुए कहा कि बुजुर्ग माता-पिता को अपनी प्रॉपर्टी में पूरी शांति, गरिमा और सुरक्षा के साथ रहने का पहला अधिकार है। यदि बेटा या बहू उनके शांतिपूर्ण जीवन में बाधा बनते हैं या खर्चा व दवाइयों की जिम्मेदारी नहीं उठाते, तो उन्हें उनके घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

हाल ही में 11 सितम्बर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जे. जे. मुनीर तथा जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने श्याम जी शुक्ला नामक बुजुर्ग द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी वरिष्ठ नागरिक की जान और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए जरूरी होने पर उसके बेटे तथा अन्य रिश्तेदार को उसके घर से निकल जाने का आदेश दिया जा सकता है। श्याम जी शुक्ला ने याचिका दी थी कि उनकी जान को अपने बेटे और बहू से खतरा है, अत: उन्हें उनके मकान से निकाला जाए।

जाहिर है कि उक्त फैसले स्पष्ट करते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार कानूनी रूप से सुरक्षित हैं और संतानों के लिए उनकी देखभाल करना नैतिक दायित्व ही नहीं बल्कि कानूनी रूप से भी बाध्यकारी है तथा बच्चों द्वारा अपनी जिम्मेदारी न निभाने पर बुजुर्गों के पास कानूनी विकल्प मौजूद हैं। आवश्यकता केवल उनका इस्तेमाल करने की है।

नई पीढ़ी को बचपन से ही माता-पिता और बुजुर्गों के प्रति आदर और सेवा भाव सिखाना जरूरी है।समाज के पीड़ित बुजुर्गों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए भावनात्मक जुड़ाव : संतानों को यह समझना होगा कि बुढ़ापे में माता-पिता को केवल पैसों की नहीं, बल्कि उनके समय और अपनेपन की जरूरत होती है

माता-पिता की सेवा करना केवल एक नैतिक कर्तव्य नहीं बल्कि हमारा कानूनी दायित्व भी है। संतानों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि आज वे जो व्यवहार अपने माता-पिता के साथ कर रहे हैं, कल उनकी अपनी संतानें भी उनके साथ वही दोहरा सकती हैं। यदि आपके आसपास कोई बुजुर्ग इस तरह की प्रताड़ना का शिकार है, तो वे सीधे राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14567 पर संपर्क करके मदद पा सकते हैं।

लेखक - मनोज कुमार अग्रवाल
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं पिछले 40 वर्ष से लेखन और पत्रकारिता से जुड़े हैं)
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य

पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप

सीएम रेखा गुप्ता ने किया रक्तदान

नई दिल्ली, 17 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में रक्तदान किया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, जनसेवा पर आपके लगातार जोर से प्रेरित होकर, हमने आज कई सरकारी पहल शुरू की हैं, जिनमें एक ब्लड डोनेशन कैंप भी शामिल है, जिसमें दिल्ली के हजारों लोग हिस्सा लेने वाले हैं। इसके अलावा, हम अंगदान के लिए एक सरकारी प्लेटफार्म लॉन्च कर रहे हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से इस पोर्टल पर पहली डोनर बनूंगी।

रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार ने यहां एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया है। जिसमें 2,500 यूनिट ब्लड इकट्ठा करने का लक्ष्य है। यह मेगा ब्लड डोनेशन कैंप पीएम नरेंद्र मोदी के जन-सेवा और राष्ट्र-सेवा के विजन को समर्पित है।

उन्होंने कहा, आज पीएम मोदी का जन्मदिन है। हमने अभी बाबा श्याम खाटू मंदिर में 108 कुंडीय हवन संपन्न किया है, जिसमें प्रधानमंत्री की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और देश की निरंतर सेवा के लिए प्रार्थना की गई है। देश और जनता की सेवा के लिए प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के बदले हम उन्हें क्या दे सकते हैं, इस पर विचार करते हुए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि यही है कि हम सभी उस रास्ते को अपनाएं और उसी के अनुसार काम करें।

सीएम ने कहा, जनसेवा पर उनके निरंतर जोर से प्रेरित होकर, हमने सरकार के नेतृत्व में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इनमें एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप भी शामिल है जिसमें दिल्ली के हजारों निवासी भाग लेंगे। हम अंगदान के लिए सरकार का पहला प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रहे हैं और मैं इस पर रजिस्टर करने वाली पहली डोनर बनूंगी।

सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर श्री खाटू श्याम विशाल मंदिर, दिल्ली धाम में आयोजित 108 कुण्डीय यज्ञ में विधिवत हवन कर उनके दीर्घ, यशस्वी और राष्ट्रसेवा को समर्पित जीवन के लिए मंगलकामना की। 17,000 ट्रस्टी इस पावन हवन में सहभागी हुए और दिव्यांग बच्चों ने सुंदरकांड का पाठ कर प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घ एवं यशस्वी जीवन की मंगलकामना की। बाबा श्याम हमारे प्रधानसेवक को निरंतर ऊर्जा, सामर्थ्य और सफलता प्रदान करें तथा राष्ट्रहित के उनके प्रत्येक संकल्प को सिद्धि मिले।

प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हवन किया

नई दिल्ली, 17 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर खाटू श्याम विशाल मंदिर दिल्ली धाम में आयोजित 108 कुण्डीय यज्ञ में विधिवत हवन कर उनके दीर्घ, यशस्वी और राष्ट्रसेवा को समर्पित जीवन के लिए मंगलकामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने त्यागराज स्टेडियम में मेगा रक्तदान शिविर में केंद्रीय राज्य मंत्री व प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा सहित दिल्ली सरकार के मंत्रियों के साथ मिलकर रक्तदान किया।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर खाटू श्याम विशाल मंदिर दिल्ली धाम में आयोजित 108 कुण्डीय यज्ञ में 17,000 ट्रस्टी सहभागी हुए और दिव्यांग बच्चों ने सुंदरकांड का पाठ कर प्रधानमंत्री के दीर्घ एवं यशस्वी जीवन की मंगलकामना की। उन्होंने कहा कि बाबा श्याम हमारे प्रधानसेवक को निरंतर ऊर्जा, सामर्थ्य और सफलता प्रदान करें तथा राष्ट्रहित के उनके प्रत्येक संकल्प को सिद्धि मिले।

संक्षिप्त वार्ता

युवा कांग्रेस ने रोजगार की मांग को लेकर शुरू किया -मेरी डिग्री का क्या-अभियान

नई दिल्ली, 17 सितंबर (वेब वार्ता)। युवा कांग्रेस ने देशभर में सरकारी विभागों में खाली पड़े करीब 50 लाख स्वीकृत पदों को एक वर्ष में भरने की मांग की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ मेरी डिग्री का क्या देशव्यापी अभियान शुरू किया है।

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरुण पांडेय ने यह जानकारी देते हुए गुरुवार को बताया कि अभियान की वेबसाइट लॉन्च की गई और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सरकारी विभागों में 50 लाख से अधिक पद खाली हैं, जबकि रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में शिक्षित युवा भटक रहे हैं।

धीरपुर में एयूडी के नए कैंपस का निर्माण जल्द

नई दिल्ली, 17 सितंबर (वेब वार्ता)। डॉ.बी. आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (एयूडी) की कुलपति प्रो. अनु सिंह लाठर ने गुरुवार को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की टीम के साथ प्रस्तावित धीरपुर कैंपस का दौरा कर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। कुलपति ने प्रस्तावित कैंपस के मानचित्र और लेआउट का अवलोकन कर भूमि और कैंपस विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अधिकारियों के साथ चर्चा की।

कुलपति ने प्रस्तावित बहुस्तरीय पार्किंग और छात्रावास से जुड़े विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी बनाए रखने और परियोजना को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी की टीम को हर 15 दिन में निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट विश्वविद्यालय को देने को कहा गया।

डूसू चुनावः डेढ़ लाख से अधिक छात्र आज करेंगे मतदान, सुरक्षा कड़ी

नई दिल्ली, 17 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव के लिए शुक्रवार को डेढ़ लाख से अधिक छात्र मतदान करेंगे। डीयू से प्राप्त जानकारी के अनुसार मतदान को लेकर विश्वविद्यालय और कॉलेजों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छात्र डूसू के चार केंद्रीय पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के लिए मतदान करेंगे। इसकी मतगणना 19 सितंबर को डीयू के स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में होगी। विश्वविद्यालय ने इसके लिए अलग से स्थल और सुरक्षा व्यवस्था की है।

डीयू से प्राप्त जानकारी के अनुसार 158 मतदान बूथ बनाए गए हैं, जहां पर 1,51,842 मतदाता मतदान करेंगे। जबकि चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और संचालन के लिए 12 कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं। कुल 1100 से अधिक ईवीएम मशीनों का प्रयोग मतदान के लिए कराया जाएगा। इसमें 830 बैलेट यूनिट और 281 सेंट्रल यूनिट ईवीएम मशीन हैं।

मुनाफे का झांसा देकर एक लाख से अधिक ठगे

नई दिल्ली, 17 सितंबर (वेब वार्ता)। शेयर ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का लालच देकर साइबर ठगों ने शाहदरा निवासी अनिल कुमार बर्मन से 1.16 लाख रुपये ठग लिए। शाहदरा साइबर थाना पुलिस ने मामले में बहादुरगढ़, हरियाणा से ललित कुमार और प्रतीक कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के एक्सिस बैंक खाते से देशभर के एनसीआरपी पोर्टल पर करीब 5000 शिकायतें, लिंक या एफआईआर जुड़ी मिली हैं।

सुपौल के लिए चलेगी विशेष रेलगाड़ी

नई दिल्ली, 17 सितंबर (वेब वार्ता)। यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली से सुपौल के बीच विशेष रेलगाड़ी का परिचालन किया जाएगा। गाड़ी संख्या 04072 नई दिल्ली से प्रतिदिन (1 अक्तूबर से 28 नवंबर तक) रात 9.35 बजे चलकर तीसरे दिन सुबह 6.35 बजे सुपौल पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04071 सुपौल जंक्शन से प्रतिदिन (3 अक्तूबर से लेकर 30 नवंबर तक) सुबह 7.45 बजे चलकर अगले दिन दोपहर 3 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।

छात्रों ने कहा, पीजी के बजाय डीयू व कॉलेज छात्रावास प्राथमिकता

नई दिल्ली, 17 सितंबर (वेब वार्ता)। सत्य निकेतन में पांच मंजिला पीजी इमारत गिरने की घटना के बाद छात्र आवास की सुरक्षा और नियमन का मुद्दा फिर सामने आया है। एसएफआई, डीवाईएफआई, डीटीएफ, एआईडीडब्ल्यूए और सीटू ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में 117 छात्रों के सर्वे के आधार पर दिल्ली में सुरक्षित, किफायती और नियमित छात्र आवास व्यवस्था की मांग की।

संगठनों का दावा है कि सर्वे में 66 फीसद छात्रों ने पीजी के बजाय विश्वविद्यालय या कॉलेज के छात्रावास को प्राथमिकता दी। वहीं, सत्य निकेतन हादसे के बाद 79 फीसद छात्रों ने वहां रहना जारी रखने को लेकर डर जताया। छात्रों ने दीवारों में दरार, खराब शीतलन व्यवस्था, लंबे समय तक मरम्मत नहीं होने, अनियमित पानी और बिजली के लिए अधिक दर वसूले जाने जैसी शिकायतें भी बताईं। संगठनों का दावा है कि सर्वे में शामिल छात्र 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं और मुख्य रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर तथा आसपास के कॉलेजों में पढ़ते हैं।

सर्वे के अनुसार, पीजी का मासिक किराया 5,000 से 30,000 रुपये तक है। डबल शेयरिंग कमरे का भोजन समेत औसत किराया करीब 14,000 रुपये बताया गया है। 31 फीसद छात्रों ने ब्रोकर के माध्यम से आवास लिया और अतिरिक्त कमीशन दिया। सुरक्षा राशि एक से तीन महीने के किराये तक है और कुछ मामलों में करीब 50,000 रुपये तक पहुंचती है।

तटरक्षक बल की 43वीं कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में समुद्री सुरक्षा पर मंथन

नई दिल्ली, 17 सितंबर (वेब वार्ता)

में भारतीय तटरक्षक बल की 43वीं कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। यह तीन दिवसीय बैठक 17 से 19 सितंबर 2026 तक तटरक्षक मुख्यालय में हो रही है। इसमें तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारी देश की समुद्री सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं।

रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने आज कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय और समुद्री सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। बैठक में तटरक्षक बल की काम करने की क्षमता, प्रशिक्षण, जरूरी सामान और सुविधाएं, कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों और प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा होगी।

तटरक्षक बल के कमांडर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के साथ भी बातचीत करेंगे। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा के मामले में तीनों बलों के बीच बेहतर तालमेल और सहयोग बढ़ाना है। कॉन्फ्रेंस में तटरक्षक बल की क्षमता बढ़ाने, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और मेक इन इंडिया के तहत चल रही परियोजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में बनी तकनीक और उपकरणों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।

निभाएी महत्वपूर्ण भूमिका

यह तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस भारतीय तटरक्षक बल की भविष्य की योजना बनाने और समुद्री सुरक्षा की प्राथमिकताएं तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

भाजपा ने सफाईकर्मी की आत्महत्या मामले में आआपा पार्षद पर आर्थिक धोखाधड़ी का लगाया आरोप

नई दिल्ली, 17 सितंबर (वेब वार्ता)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी (आआपा) के त्रिलोकपुरी से निगम पार्षद विजय कुमार पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के सफाई कर्मी दीपक के साथ आर्थिक धोखाधड़ी करने और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में इस मामले में दर्ज पुलिस एफआईआर को सार्वजनिक करते हुए कहा कि घटना ने आम आदमी पार्टी का दोहरा चेहरा उजागर किया है।

हर्ष मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि सफाई कर्मी दीपक त्रिलोकपुरी वार्ड में कई वर्षों से कार्यरत थे और अपने परिवार के लिए मकान बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पार्षद विजय कुमार से मदद मांगी थी। उन्होंने बताया कि करीब एक वर्ष पहले पार्षद ने दीपक को मकान दिलाने का भरोसा देकर 15 लाख रुपये का ऋण दिलवाया और कथित तौर पर राशि अपने खाते में स्थानांतरित करवा ली। मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि दीपक की हस्ताक्षरित चेकबुक पार्षद ने अपने पास रख ली थी और पिछले नौ-दस महीनों से उनके वेतन की राशि भी चेक के माध्यम से निकालते थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि दीपक लगातार मकान दिलाने या पैसा वापस करने की मांग कर रहे थे, लेकिन कथित तौर पर उन्हें धमकाया गया और 25 प्रतिशत कमीशन की मांग की गई। मल्होत्रा ने कहा कि आर्थिक परेशानी के कारण दीपक मानसिक रूप से परेशान रहने लगे और अपने परिजनों एवं मित्रों से कहते थे कि उन्हें कुछ होने पर इसके लिए पार्षद विजय कुमार जिम्मेदार होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दीपक ने एक सितंबर को आत्महत्या कर ली। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद भी पार्षद की ओर से परिवार को डराने-धमकाने का प्रयास किया गया। मामले की जानकारी 7-8 सितंबर के आसपास भाजपा नेताओं को हुई, जिसके बाद विधायक रविकांत, विधायक रविन्द्र नेगी, पार्षद प्रियंका गौतम और पूर्व उपमहापौर राजकुमार ढिल्लों ने परिवार से संपर्क किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में मदद की।

सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में किरण बेदी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

नई दिल्ली, 17 सितंबर (वेब वार्ता)। पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर सत्य निकेतन में एक छात्रावास की इमारत ढहने के मामले में उन्हें पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध किया। इस घटना में सात लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें अधिकतर छात्र थे।

केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने हालांकि बेदी की याचिका का विरोध किया और आपत्तियां दाखिल करने के लिए समय मांगा।

मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने विधि अधिकारी से कहा, आप क्या जवाब दाखिल करेंगे? वह देश की एक जिम्मेदार नागरिक हैं। उनके पास प्रशासनिक अनुभव है। यह मामला व्यापक जनहित से जुड़ा हुआ है। शर्मा ने कहा कि वह बेदी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हस्तक्षेप के अनुरोध संबंधी उनकी याचिका से

यह प्रतीत होता है कि वह उस मामले में ह्लपहले ही निष्कर्ष पर पहुंच रही हैं, जिसमें अधिकारियों को अभी वस्तु स्थिति रिपोर्ट दाखिल करनी है।

अदालत ने अधिकारियों से इसे प्रतिकूल रूप से नहीं लेने को कहा और उन्हें बेदी की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय दिया। मामले की सुनवाई मुख्य याचिका के साथ 25 सितंबर को होगी।

अदालत ने कहा था कि यह घटना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि इसने अपर्याप्त आवास सुविधाओं (जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा संचालित छात्रावास शामिल हैं), छात्रों की सुरक्षा और संरक्षा, तथा ऐसे पीजी आवासों को विनियमित करने के लिए एमसीडी और अन्य अधिकारियों द्वारा उठाए गए नाकाफी उपायों को लेकर गहरी चिंता पैदा कर दी है।

सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती

सत्य निकेतन स्थित इमारत छह सितंबर को मरम्मत कार्य के दौरान ढह गई थी। इस घटना में सात लोगों की मौत हो गई थी और सात अन्य घायल हो गये थे। उच्च न्यायालय ने सात सितंबर को इस घटना की उच्चस्तरीय एमसीडी जांच का आदेश दिया था और यह स्पष्ट किया था कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

सत्य निकेतन हादसे के मृतकों की तेरहवीं से पहले मोदी का जन्मदिन मनाने पर आप ने भाजपा को घेरा

नई दिल्ली, 17 सितंबर (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी (आप) ने सत्य निकेतन पीजी हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों की तेरहवीं से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाए जाने को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को आरोप लगाया कि सत्य निकेतन में मातम के बीच भाजपा प्रधानमंत्री का जन्मदिन दिवाली की तरह मना रही है। उन्होंने कहा कि 18 सितंबर को हादसे में मृत छात्रों की तेरहवीं है और ऐसे समय में जश्न मनाना असंवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने एक्स पर साझा एक वीडियो में कहा कि छह सितंबर को सत्य निकेतन पीजी में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों समेत सात लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने कहा कि हिंदू सनातन रीति-रिवाजों के अनुसार 18 सितंबर को मृतकों की तेरहवीं होनी है। उन्होंने दावा किया कि तेरहवीं तक सूतक का समय माना जाता है और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर हर्षोल्लास से कार्यक्रम आयोजित करना उचित नहीं है। उन्होंने देशवासियों और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से इस घटनाक्रम पर ध्यान देने की अपील की।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया नमो श्रमिक सेवा केंद्र और गिग वर्कर्स विश्राम स्थल का उद्घाटन

नई दिल्ली, 17 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को शालीमार के हैदरपुर में नमो श्रमिक केंद्र और गिग वर्कर्स विश्राम स्थल का उद्घाटन किया। इस मौके पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज हम भगवान विश्वकर्मा की जयंती मना रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर भारत के विकास के शिल्पकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन है। मैं भगवान विश्वकर्मा के चरणों में प्रार्थना करती हूं कि वो पीएम मोदी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें।

रेखा गुप्ता ने कहा कि आज इस शुभारंभ से श्रमिकों को राहत और कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। श्रमिक सेवा केंद्र के जरिए श्रमिकों को केंद्र और दिल्ली सरकार की सभी योजनों का लाभ मिलेगा। साथ ही श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के 25 रुपए की फीस को हटाकर निशुल्क कर दिया गया है और जल्द श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नमो श्रमिक सेवा केंद्र में शुरू होगी।

उन्होंने कहा कि जल्द श्रमिकों के स्किल सेंटर भी शालीमार में जल्द खोला जाएगा और उसके बाद दिल्ली के अलग अलग जगहों पर इन्हें खोला जाएगा। लगभग 34 सेंटर और जल्द खोले जाएंगे। गिग वर्कर विश्राम स्थल में ठंडे पानी, मोबाइल चार्ज और छोटे बच्चों के लिए बेबी सिटिंग व्यवस्था होगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज से स्किल डेवलपमेंट के कई श्रमिकों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। दिल्ली सरकार देश के बाहर काम करने के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ भाषा सीखने का काम भी करेगी। वहीं, दिल्ली सरकार में कपिल मिश्रा ने कहा, ह्लभगवान विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्रमिकों के लिए निशुल्क रजिस्ट्रेशन पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जगह-जगह रजिस्ट्रेशन ऑफिस खोले जाएंगे। अब रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लगेगी। कोई भी श्रमिक रजिस्ट्रेशन जाकर निशुक्ल रजिस्ट्रेशन करा सकता है।

उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प के तहत पूरी दिल्ली में 34 नमो श्रमिक सेवा केंद्र और गिग वर्कर्स विश्राम स्थल का ऐतिहासिक शुभारंभ किया जा रहा है।

एनएसयूआई ने डूसू चुनाव से पहले जंतर-मंतर तक ताली-थाली मार्च निकाला

नई दिल्ली, 17 सितंबर (वेब वार्ता)। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने बृहस्पतिवार को छात्रों और दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) समुदाय से जुड़े मुद्दों को लेकर अपने मुख्यालय रायसीना रोड से जंतर-मंतर तक ह्यताली-थाली मार्चह्न निकाला।

एनएसयूआई के अनुसार, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में मार्च दोपहर दो बजे पांच रायसीना रोड स्थित संगठन के मुख्यालय से शुरू हुआ। एनएसयूआई के एक सदस्य ने कहा, इस मार्च के जरिए दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावास उपलब्ध कराने और देशभर में प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ कार्रवाई जैसी मांगों को उठाया जा रहा है।

यह मार्च दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव से एक दिन पहले निकाला गया। चुनाव शुक्रवार को होने हैं। दिन की पाली के लिए मतदान सुबह 8:30 बजे से दोपहर एक बजे तक होगा, जबकि शाम की पाली के लिए मतदान दोपहर तीन बजे से शाम 7:30 बजे तक होगा। मतगणना 19 सितंबर को नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के खेल स्टेडियम के बहुउद्देश्यीय हॉल में की जाएगी।

संक्षिप्त वार्ता

हरदोई में बाढ़ में डूबी दशकों पुरानी पुलिया बनी काल

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। खेत का हाल देखकर घर लौट रहे करीब 35 वर्षीय युवक की जिंदगी सुखेता नदी की बाढ़ में समा गई। शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के मिठनापुर गांव निवासी सचिन कुमार सिंह पुत्र बाबू सिंह खेत देखकर वापस घर आ रहे थे। सुखेता नदी पर बनी पुलिया से गुजरते समय अचानक उनका पैर फिसल गया और वह बाढ़ के पानी में जा गिरे। देखते ही देखते वह नदी की गहराई में समा गए। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। नदी में युवक के डूबने की खबर से अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय गोताखोरों ने तत्काल नदी में उतरकर तलाश शुरू की। काफी प्रयास के बाद सचिन कुमार सिंह को नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

टूटी सड़कों को मरम्मत का इंतजार, अच्छी सड़क पर बिछा दी नई सीसी सड़क

वेब वार्ता, आलोक चतुर्वेदी

ललितपुर। शहर में सड़क निर्माण को लेकर नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि जहां कई इलाकों में बदहाल सड़कों को

मरम्मत और निर्माण का इंतजार है, वहीं वार्ड नंबर 26 महावीरपुरा के मऊठाना में जैन नया मंदिर के पास पहले से अच्छी हालत में मौजूद सड़क पर दोबारा सीसी सड़क का निर्माण करा दिया गया। नगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हरिबाबू शर्मा ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर उक्त निर्माण कार्य की जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि जैन नया मंदिर के पास सड़क पहले से ही अच्छी स्थिति में थी, इसके बावजूद वहां नई सीमेंट-कंक्रीट सड़क डाल दी गई। इससे सड़क की ऊंचाई बढ़ गई है और स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है।

डैमेज में राहत का मौका, ईपीएफओ कानपुर ने 650 से अधिक प्रतिष्ठानों को जारी किए पत्र

कानपुर। ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर द्वारा विश्वास योजना-2026 के तहत 650 से अधिक प्रतिष्ठानों को पत्र जारी कर उन्हें योजना के अंतर्गत पात्रता एवं उपलब्ध लाभों की जानकारी दी गई है। पत्रों के माध्यम से प्रतिष्ठानों को बताया गया है कि वे लंबित डैमेज से संबंधित मामलों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार योजना का लाभ उठाकर अपने मामलों का निस्तारण करा सकते हैं।

ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त शाहिद इकबाल ने बताया कि योजना का लाभ उठाते हुए अब तक 7 प्रतिष्ठानों द्वारा 12 लाख रुपये से अधिक का लाभ प्राप्त किया जा चुका है। इससे अन्य पात्र नियोक्ताओं के लिए भी अपने लंबित डैमेज मामलों के निस्तारण का महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध है। ईपीएफओ ने ऐसे सभी नियोक्ताओं से अपील की है, जिनके प्रतिष्ठानों पर डैमेज की राशि लंबित है, कि वे विश्वास योजना-2026 के इस विशेष अवसर का लाभ उठाते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें। योजना के अंतर्गत पात्र मामलों में डैमेज की दर में निर्धारित राहत का प्रावधान है, जिससे नियोक्ताओं को अपने लंबित मामलों के समाधान का अवसर मिल सकता है।

प्रमाण पत्र की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर गरजा गिहार समाज

वेब वार्ता, मुरादाबाद। राष्ट्रहित इंडियन पार्टी सेकुलर ने गिहार जाति की विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को पेश किया गया जिसमें 13 सूत्रीय मांगों को उजागर किया गया है।

ज्ञापन में कहा गया है कि भारत को आजाद हुए लगभग 80 वर्ष हो गए उत्तर प्रदेश में गिहार जाति की संख्या 2 से 3 करोड़ होने के बावजूद भी गिहार जाति को उत्तर प्रदेश सरकार शासनादेश में सूचीबद्ध नहीं किया गया है अनेकों बार भारत सरकार को प्रदेश से प्रस्ताव भेजा गया लेकिन अनुसूचित जनजाति कार्य मंत्रालय भारत के महा पंजीयन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रस्ताव को निरस्त किया गया जबकि गिहार जाति में कानूनी तौर पर जनजाति के सभी मानक लक्षण पूर्ण हैं ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में नगर निगम द्वारा हैलेट रोड कपूर कंपनी स्थित एससी एसटी के लोगों की 100 वर्ष पुरानी झुग्गी झोपड़ियां को हटाया जा रहा है इस नगर निगम की इस कार्यवाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाने की मांग उठाई गई है यह भी कहा गया है कि यहां स्थित हिंदू समुदाय की 100 वर्ष पुरानी भूमि मंदिर कुआं देवी देवताओं की मूर्तियां आदि हुआ करती थी इस कुएं पर बच्चों का मुंडन भी किया जाता था और भसौड़ा मेला भी लगता था पर वहां मौजूद कट्टरपंथियों ने पिछले कई वर्षों से गुंडई के बल पर अवैध कब्जा कर लिया है।

सात से अधिक सीट वाले निजी वाहनों को बड़ी राहत

अब फिटनेस टेस्ट की अनिवार्यता खत्म

कानपुर। शासन ने अब निजी वाहन स्वामियों को जिनके पास सात से अधिक सीट वाले वाहन है, उन्हें फिटनेस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया है। शासन के दिशा-निर्देशों के क्रम में परिवहन विभाग ने निजी वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है।

वेब वार्ता, हरी शंकर शर्मा

> परिवहन आयुक्त ने वर्ष 2005 का पुराना आदेश किया निरस्त

> कानपुर नगर में 18584 वाहनो को मिली फिटनेस बाध्यता से मुक्ति

परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब केवल सीट क्षमता (ड्राइवर को छोड़कर 7 से 9 सीट) के आधार पर निजी वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र की बाध्यता नहीं होगी। इस सेवा प्रभावी होने पर कानपुर नगर में 18584 वाहनो को अब फिटनेस की जांच कराने और प्रमाणपत्र अनिवार्यता से छूट मिल गई

एआरटीओ प्रशासन कहकशां खातून ने स्पष्ट किया कि पहले वाहन खरीदने के 8 वर्ष बीत जाने के बाद प्रत्येक 2 वर्ष में संभागीय निरीक्षक (प्राविधक) से फिटनेस जांच कराना अनिवार्य था।

इस बाध्यता के समाप्त होने से वाहन मालिकों का समय और पैसा दोनों बचेगा।

हालांकि, मोटर यान अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के तहत सुरक्षा नियम और कानूनी दायित्व पहले की तरह ही लागू रहेंगे।

ऑटो अप्रूवल मोड: राहत के साथ चुनौतियां

मोर्थ की गाइडलाइन के तहत परिवहन विभाग की 50 से अधिक सेवाओं को फेसलैस और ऑटो अप्रूवल मोड पर डाल दिया गया है। एआरटीओ कहकशां खातून और आरआई संतोष कुमार के अनुसार इन सेवाओं के ऑटो मोड पर हो जाने से इसका लाभ आवेदकों को मिलेगा उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़गें और काम तुरंत हो जायेगा। लेकिन अगर दूसरा पहूल देखा जाये तो भौतिक सत्यापन न होने के कारण व्यवस्था में कागजी गड़बड़ियों और तकनीकी खामियों की गुंजाइश बनी रहेगी।

आरटीओ परिसर में दलालों पर सख्त कार्रवाई

कार्यालय में पारदर्शिता बनाए रखने और दलालों के प्रवेश को रोकने के लिए एआरटीओ प्रशासन कहकशां खातून और आरआई संतोष कुमार ने आरटीओ परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अनाधिकृत रूप से मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। अधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ किया कि परिसर में केवल काम से आए वास्तविक आवेदकों को ही प्रवेश दिया जाएगा।

भूमाफियाओं पर सरकार कसे शिकंजा: ठाकुर धर्मेंद्र सिंह

मुरादाबाद, वेब वार्ता

महाशक्तिभारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व जेल विजिटर हाजी मोहम्मद इदरीस सहित अन्य पदाधिकारीयों के साथ जिलाधिकारी को एक ज्ञापन पेश किया साथ ही किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को भी ज्ञापन पेश किए गए।

जिलाधिकारी को पेश किए गए ज्ञापन में कहा गया है कि मुरादाबाद सदर तहसील अंतर्गत ग्राम अक्का डिलारी की गाटा संख्या 258 क एवं गाटा संख्या 249 व 250 पर एसडीएम सदर के आदेश के बावजूद भी भू माफिया किस्म के व्यक्ति राजपाल खूब सिंह एवं जयपाल आदि दर्जनों लोगों ने पार्टी कार्यकताओं की भूमि पर कब्जा कर लिया है ज्ञापन में कहा गया है कि यह लोग पूर्व में पार्टी कार्यकर्ता ओम प्रकाश आदि पर जानलेवा हमला कर चुके हैं ज्ञापन के माध्यम से दबंग भू माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की मांग उठाई गई है कार्यवाही न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व जेल विजिटर हाजी मोहम्मद इदरीस ने एसडीएम सदर तहसीलदार एवं सी ओ सिविल लाइन को भी किसानों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन पेश करके शीघ्र समाधान कराए जाने की मांग उठाई है प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद इदरीस ने कहा कि मुरादाबाद देहात ग्रामीण क्षेत्र पीपलसाना भोजपुर में बिजली कटौती की समस्या से किसान परेशान है इसके अलावा क्षेत्रीय किसानों की विभिन्न समस्याओं को भी उजागर किया गया संबंधित अधिकारियों द्वारा शीघ्र समाधान कराए जाने का आश्वासन दिया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद इदरीस के अलावा नईम अंसारी मोहम्मद अहसान एवं मोहम्मद आतिफ आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।

कोलकाता के बाद लॉस एंजेलिस पहुंची हरदोई के क्रांतिकारी जयदेव कपूर की कहानी

19 सितंबर को शहीद दिवस पर होगा विमोचन

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। हरदोई के महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद जयदेव कपूर की जिंदगी, संघर्ष और आजादी की लड़ाई में उनके योगदान की कहानी अब अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंच रही है। उनके जीवन पर आधारित वीडियो एल्बम जयदेव कपूर ए हिडन फ्रीडम फाइटर ने कोलकाता के बाद अमेरिका के लॉस एंजेलिस तक अपनी दस्तक दी है। एल्बम का चयन न्यूवेव एआई फिल्म फेस्टिवल 2026 में हुआ है।

इससे पहले एल्बम को 5वें इंटरनेशनल टैगोर फिल्म अवॉर्ड्स 2026, कोलकाता के लिए ऑफिशियल सेलेक्शन प्राप्त हुआ था। जारी प्रमाणपत्र के अनुसार फिल्म को अक्टूबर 2026 में कोलकाता में होने वाले समारोह के लिए चयनित किया गया है। इसके बाद लॉस एंजेलिस के न्यूवेव एआई फिल्म फेस्टिवल में शामिल होना इस परियोजना की अंतरराष्ट्रीय यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।

फेस्टिवल से संबंधित पोस्टर में लॉस एंजेलिस में हॉलीवुड एवं टेक इंडस्ट्री पैनल, एआई फिल्म निर्माण तथा चयनित शीर्ष एआई फिल्मों की स्क्रीनिंग जैसे कार्यक्रमों का उल्लेख है। ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर हरदोई के एक क्रांतिकारी की कहानी का पहुंचना जिले की ऐतिहासिक विरासत के लिए उल्लेखनीय है।

अभिलेखों से स्क्रीन तक पहुंची क्रांतिकारी की कहानी

रेडियो जागो 90.4 एफएम, हरदोई की अभिरक्षा में शहीद जयदेव कपूर से संबंधित लिखित अभिलेखों के माध्यम से भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों के योगदान से जुड़े उन अनसुने प्रसंगों को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जयदेव कपूर की जुबानी उनकी कहानी के माध्यम से इन संस्मरणों और अभिलेखों को नई पीढ़ी तथा व्यापक समाज तक पहुंचाने की पहल की जा रही है।

हरदोई में सेवा संकल्प अभियान के तहत 50 दिव्यांगजनों को मिले सहायक उपकरण

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिला प्रशासन की ओर से गुरुवार को श्रीश चंद्र बारात घर में लाभार्थीपरक योजनाओं के प्रमाण पत्र और दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार आबकारी एवं मद्यनिषेध नितिन अग्रवाल रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन की मौजूदगी में कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन से हुआ।

विभिन्न विभागों की योजनाओं के चयनित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, प्रमाण पत्र और सहायता सामग्री दी गई। उद्योग विभाग ने 10 लाभार्थियों को टूलकिट, दिव्यांगजन पेंशन योजना के 10 नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के पांच लाभार्थियों को आवास की चाबी और 15 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। स्वास्थ्य विभाग ने 10 दिव्यांगजनों को यूडीआईडी प्रमाण पत्र दिए। मुख्यमंत्री बाल सेवा एवं स्पॉन्सरशिप योजना के पांच लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र अथवा प्रमाण पत्र और जिला पूर्ति विभाग ने पांच पात्र लाभार्थियों को अन्त्योदय राशन कार्ड वितरित किए।

सबसे अधिक उत्साह दिव्यांगजनों के बीच देखने को मिला। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से 50 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, सामान्य ट्राइसाइकिल समेत विभिन्न सहायक उपकरण दिए गए। उपकरण मिलने के बाद लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। राज्यमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद कर उनकी जरूरतों और अनुभवों की जानकारी ली।

नितिन अग्रवाल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र और जरूरतमंद व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण देकर उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने में सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी नेहा ब्याडवाल, नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय निगम, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी शशांक सिंह सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, लाभार्थी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मनीष मिश्रा ने किया।

इससे पूर्व राज्यमंत्री नितिन अग्रवाल ने स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से रक्तदान कर सेवा संकल्प अभियान को सफल बनाने की अपील की। पुलिस लाइन में भी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया।

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर काशी में जुटे भाजपा और एनडीए के दिग्गज

बाबा विश्वनाथ से मांगा स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद

वेब वार्ता/अजय कुमार

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर गुरुवार को काशी में भाजपा और एनडीए के दिग्गज जुटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा-अर्चना की। मंदिर के अर्चक श्रीकांत शर्मा ने षोडशोपचार विधि से पूजन संपन्न कराया। सभी ने बाबा विश्वनाथ से प्रधानमंत्री मोदी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना की। यह आयोजन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के तहत हुआ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हम सभी के लिए गौरव और सौभाग्य का दिन है। भारत के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बाबा विश्वनाथ धाम में पूजन कर उनके स्वस्थ रहने की कामना की गई। यहां के पुरोहितों और आचार्यों का सम्मान किया गया। बड़नगर से काशी तक बाइक रैली में शामिल बाइकर्स से संवाद कर प्रसाद वितरित किया गया। इसके साथ ही श्री काशी विश्वनाथ धाम में सेवा देने वाले सफाई कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया।

17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से शुरू हुआ सेवा संकल्प अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इसी अभियान के तहत काशी में विशेष पूजन-अर्चन, बटुकों और तीर्थ पुरोहितों के सम्मान, स्वच्छता प्रहरियों के नागरिक अभिनंदन और बड़नगर से काशी पहुंचे बाइकर्स से संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

बटुकों और तीर्थ पुरोहितों का सम्मान

विशेष पूजन के बाद मंदिर परिसर में मंगलाचरण करने वाले बटुकों और तीर्थ पुरोहितों का सम्मान किया गया। उन्हें अंगवस्त्रम और दक्षिणा प्रदान की गई। विश्वनाथ धाम में सेवा देने वाले स्वच्छता प्रहरियों का भी नागरिक अभिनंदन किया गया। उन्हें प्रसाद, अंगवस्त्रम और दक्षिणा भेंट की गई। सम्मान और प्रसाद की सामग्री पर्यावरण अनुकूल जूट के झोलों में वितरित की गई।

प्रधानमंत्री आजीवन स्वस्थ रहें : राजनाथ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर काशी में पूजा-अर्चना की गई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के आजीवन स्वस्थ रहने की कामना की, ताकि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

देश को प्रधानमंत्री मोदी पर गर्व : नायडू

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाना खुशी और गर्व की बात है। देश को प्रधानमंत्री मोदी पर गर्व है और उन्होंने देश को बहुत गौरव दिलाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। कार्यक्रम में सेवा संकल्प यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक बीडी शर्मा और बनारस यात्रा के संयोजक जेपीएस राठौर समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर गरजा गिहार समाज

मुरादाबाद (वेब वार्ता)। राष्ट्रहित इंडियन पार्टी सेकुलर ने गिहार जाति की विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को पेश किया गया जिसमें 13 सूत्रीय मांगों को उजागर किया गया है।

ज्ञापन में कहा गया है कि भारत को आजाद हुए लगभग 80 वर्ष हो गए उत्तर प्रदेश में गिहार जाति की संख्या 2 से 3 करोड़ होने के बावजूद भी गिहार जाति को उत्तर प्रदेश सरकार शासनादेश में सूचीबद्ध नहीं किया गया है अनेकों बार भारत सरकार को प्रदेश से प्रस्ताव भेजा गया लेकिन अनुसूचित जनजाति कार्य मंत्रालय भारत के महा पंजीयन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रस्ताव को निरस्त किया गया जबकि गिहार जाति में कानूनी तौर पर जनजाति के सभी मानक लक्षण पूर्ण हैं ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में नगर निगम द्वारा हैलेट रोड कपूर कंपनी स्थित एससी एसटी के लोगों की 100 वर्ष पुरानी झुग्गी झोपड़ियां को हटाया जा रहा है।

थैलेसीमिया स्क्रीनिंग में नया अलर्ट

कानपुर क्षेत्र में एचबीई वैरिएंट की दिखी महत्वपूर्ण मौजूदगी

कानपुर। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर के पैथोलॉजी विभाग में हुए शोध अध्ययन में पुष्ट हीमोग्लोबिन विकारों में एचबीई ट्रेट की हिस्सेदारी लगभग 11 फीसदी यानी लगभग (10.8ः) पाई गई है। यह खोज बदलते क्षेत्रीय व जनसांख्यिकीय रुझानों तथा प्रसवपूर्व (एएनसी) व विवाह-पूर्व एचपीएलसी जांच के महत्व को दर्शाता है।

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने विभाग को इस महत्वपूर्ण शोध के लिए बधाई दी और कहा कि प्रसूता महिलाओं में जांच इस रोग को नियंत्रित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा शादी से पहले एचपीएलसी जांच कराना, इस प्रकार के रक्त विकार को रोकने के लिए अचूक उपाय है।

यह शोध कार्य डॉ. पूजा सैनी (एमडी रेजिडेंट) द्वारा डॉ. सुनीता (एसोसिएट प्रोफेसर) एवं विभागाध्यक्ष व सह-गाइड डॉ. लुबना खान (प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष), पैथोलॉजी विभाग, जी.एस.वी.एम. मेडिकल कॉलेज, कानपुर व अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के मार्गदर्शन में किया गया। विभागाध्यक्ष डॉ. लुबना खान एवं डॉ. सुनीता ने बताया कि उत्तर भारत में चिकित्सकों एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों को एनीमिया के मूल्यांकन के दौरान एचबीई की संभावना को भी ध्यान में रखना चाहिए। गर्भावस्था में प्रारंभिक एचपीसीएल जांच और उसके उपरांत पति (जीवनसाथी) की अनिवार्य स्क्रीनिंग से भविष्य में जन्म लेने वाले बच्चों में गंभीर कंपाउंड हीमोग्लोबिनोपैथी की प्रभावी रोकथाम संभव है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष एवं वैज्ञानिक बिंदु

उत्तर भारत में हीमोग्लोबिन एचबीई को मुख्य रूप से पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत का स्थानिक विकार माना जाता रहा है। लेकिन कानपुर में 83 पुष्ट मामलों में एचबीई ट्रेट 10.8 फीसदी दर्ज हुआ। कंपाउंड एचबीई-बीटा-थैलेसीमिया को मिलाकर यह आंकड़ा 12 फीसदी से अधिक रहा, जो जनसांख्यिकीय आवागमन और आनुवंशिक मिश्रण की पुष्टि करता है। एचबीई ट्रेट से प्रभावित सभी मरीज पूरी तरह लक्षणहीन (100 फीसदी) थे और हीमोग्लोबिन स्तर सामान्य (9.44 0.31 जी/डीएल) के करीब था। हालांकि, जब इसका सह-उत्तराधिकार क्षेत्र में सबसे आम बीटा-थैलेसीमिया ट्रेट के साथ होता है, तो यह गंभीर कंपाउंड एचबीई-बीटा-थैलेसीमिया का रूप ले लेता है, जिससे बच्चों में अत्यंत गंभीर एनीमिया (5.55 जी/डीएल) और शारीरिक विकास में रुकावट होती है। प्रसवपूर्व एवं विवाह-पूर्व जांच की प्राथमिक में लगभग 70 फीसदी मामले गर्भावस्था के दौरान नियमित एनसी जांच में ही सामने आए। चूंकि लक्षणहीन वाहक सामान्य दिखते हैं, इसलिए विवाह-पूर्व तथा प्रसवपूर्व एचपीएलसी जांच ही भावी पीढ़ी को इस गंभीर आनुवंशिक विसंगति से बचाने का सर्वोत्तम उपाय है।

टीएमसी का नाम-निशान फ्रीज कर सकता है चुनाव आयोग

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के दोनों गुटों के बीच पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दोनों गुट 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव में उतरने की तैयारी में हैं, लेकिन संभावना है कि वे तृणमूल कांग्रेस के नाम और मौजूदा चुनाव चिह्न के साथ चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर खींचतान तेज हो गई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख बुधवार को थी, इसी दिन चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को पत्र भेजकर दोपहर 3 बजे तक अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने को कहा।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने बताया कि ऐसे मामलों में फैसला लेने में समय लगता है। अगर चुनाव नजदीक हो तो आयोग आमतौर पर पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को फ्रीज कर देता है। इसके बाद दोनों गुटों को अस्थायी नाम और चुनाव चिह्न आवंटित किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने भी

इसी संभावना से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में आम तौर पर आयोग चुनाव चिह्न को फ्रीज करता है और इसके लिए कई स्तरों पर निर्णय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।चुनाव आयोग दोनों गुटों से अतिरिक्त दस्तावेज मांग चुका है। आयोग दोनों पक्षों को एक बार फिर सुनवाई के लिए बुला सकता है। रघुनाथगंज के विधायक अखरुज्जमां ने बताया कि आयोग ने अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने के लिए दोपहर 3 बजे तक का समय दिया था और उन्हें यह भी बताया गया कि गुरुवार को एक और सुनवाई हो सकती है। उनके मुताबिक, चुनाव चिह्न का आवंटन 19 सितंबर तक पूरा होना जरूरी है। पिछले शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग की पूरी पीठ ने दोनों गुटों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। एक गुट का नेतृत्व तृणमूल की संस्थापक और बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं, जबकि दूसरे गुट की अगुवाई बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता रितब्रत बनर्जी कर रहे हैं। दोनों गुटों ने आयोग से अपील की थी कि उपचुनाव से पहले तृणमूल के चुनाव चिह्न और पार्टी की संपत्तियों पर दावों को लेकर फैसला किया जाए। ममता बनर्जी के करीबी एक तृणमूल नेता ने आयोग पर जानबूझकर जटिलताएं पैदा करने का आरोप भी लगाया।

महाराष्ट्र के आदिवासी छात्रावासों में यौन शोषण का आरोप

नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आदिवासी छात्र-छात्राओं से बातचीत की। इस दौरान छात्राओं ने आदिवासी छात्रावासों से जुड़ी कई गंभीर परेशानियां बताईं, जिसमें यौन शोषण की शिकायतें भी शामिल हैं।

छात्राओं ने प्रेग्नेंसी टेस्ट की भी शिकायत की

छात्राओं ने कई मामलों में जबरन प्रेग्नेंसी टेस्ट कराए जाने का भी आरोप लगाया है। अभिजीत दीपके 17 सितंबर से आदिवासी स्कूलों का दौरा करने की एक नई मुहिम शुरू कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने बुधवार को आदिवासी छात्राओं से भी बात की, जिन्होंने खुलकर अपनी परेशानियां बताईं। कई छात्राओं ने बताया कि अधिकांश आदिवासी आश्रम स्कूलों में बच्चियों के साथ यौन शोषण हो रहा है।

दीपके के साथ बुधवार को हुई बातचीत में विदर्भ और मराठवाड़ा जिलों की कई छात्राएं शामिल हुईं थीं। छात्राओं ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपियों को बचाने के लिए आदिवासी समुदाय के बच्चों को आरोपी बना दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सरकारी आदिवासी स्कूलों में सुविधाओं की कमी भी बताई। इस दौरान एक छात्रा ने खासतौर पर भंडारा के हॉस्टल का जिक्र किया, जहां 15 लड़कियों को एक ही कमरे में रखा जाता है। कई छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि आश्रम स्कूलों में बच्चियों को जबरन प्रेग्नेंसी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा, वॉशरूम के इस्तेमाल और स्कॉलरशिप सहित अन्य परेशानियां भी गिनाईं। नागपुर स्थित आदिवासी विकास भवन में कई छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपके ने आदिवासी छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है और कहा है कि वह राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में उतरेंगे। उन्होंने बच्चों को अपनी परेशानियों की जानकारी फैलाने और इसके लिए व्हाट्सऐप ग्रुप बनाने की सलाह दी। दीपके ने बुधवार को आदिवासी स्कूल ठीक करो अभियान की 17 सितंबर से शुरूआत का ऐलान किया है। इससे पहले उनकी पार्टी स्कूल ठीक करो अभियान चला रही थी। उन्होंने कहा कि पिछले 80 वर्षों में सभी सरकारों ने देशभर के आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों की उपेक्षा की है। इसलिए वे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। दीपके ने सरकारों पर आदिवासी छात्रों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक दल अपने मुख्यालयों पर करोड़ों खर्च करते हैं, लेकिन आदिवासी आवासीय विद्यालयों के लिए धन नहीं है, जो अक्सर किराये की इमारतों से चलते हैं। उन्होंने सरकार से आदिवासी समुदाय को प्राथमिकता देने की अपील की, क्योंकि केवल जीडीपी वृद्धि या अर्थव्यवस्था के आकार की बात करना पर्याप्त नहीं है।

केरल के पारंपरिक पप्पडम निर्माता नए नियमों से परेशान

तिरुवनंतपुर। गर्म तेल में डालते ही गुब्बारे की तरह फूलने वाला पप्पडम अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए नियम को लेकर चर्चा में है।

केरल की पारंपरिक खाद्य हो या बिरयानी, भोजन की थाली में रखा पतला, सुनहरा और कुरकुरा पप्पडम यानी पापड़ यहां के खान-पान का अहम हिस्सा है।भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए नियम में देशभर में तैयार होने वाले सभी प्रकार के पापड़ों में नमी की अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत तय की गई है। इसको लेकर केरल के पप्पडम निमार्ताओं का कहना है कि यह सीमा केरल की पारंपरिक पप्पडम बनाने की प्रक्रिया के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। केरल के पारंपरिक पप्पडम में नमी की मात्रा सामान्य तौर पर 15 से 16 प्रतिशत के आसपास बताई जाती है। इसके मुकाबले उत्तर भारत के मसाला पापड़ और तमिलनाडु तथा कर्नाटक में बनाए जाने वाले अप्पलम में नमी की मात्रा करीब 10 से 12 प्रतिशत रहती है। कम नमी के कारण इन उत्पादों की टिकने की क्षमता भी अधिक होती है। दूसरी ओर, केरल के पप्पडम की खासियत उसकी बनावट और तलने के बाद

फूलने की प्रक्रिया में मानी जाती है।

निमार्ताओं के अनुसार पप्पडम में मौजूद नमी जब गर्म तेल के संपर्क में आती है तो तेजी से भाप में बदलती है। इस प्रक्रिया के कारण पप्पडम के भीतर दबाव बनता है और वह फूल जाता है। इसी से इसकी विशेष बनावट, बुलबुलेदार सतह और कुरकुरापन मिलता है। निमार्ताओं का दावा है कि यदि नमी की मात्रा 15 प्रतिशत से नीचे कर दी गई तो पारंपरिक पप्पडम का वह स्वरूप और बनावट प्रभावित हो सकती है, जिसके लिए यह लोकप्रिय है। केरल पप्पडम निमार्ताओं के संगठन ने नए नियम को लेकर चिंता जताई है। संगठन का कहना है कि देश के अलग-अलग क्षेत्रों में पापड़ बनाने की पारंपरिक विधियां और उनकी विशेषताएं अलग हैं। ऐसे में सभी प्रकार के पापड़ों के लिए एक समान नमी सीमा तय करना उचित नहीं है।

निमार्ताओं का यह भी कहना है कि निर्धारित सीमा से अधिक नमी पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से कार्रवाई और जुर्माने की स्थिति बन रही है। संगठन ने राज्य के खाद्य मंत्री और संबंधित वैज्ञानिक समिति से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। पप्पडम को लेकर सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई लोग इसे केरल की खान-पान की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए इसके पारंपरिक स्वरूप को बचाने की बात कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, केरल में प्रतिदिन करीब 70 लाख पप्पडम की बिक्री होती है। ऐसे में इस नियम का असर केवल निमार्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य की पारंपरिक खाद्य संस्कृति से भी जुड़ सकता है।

सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, दो आतंकी ढेर; सर्च ऑपरेशन जारी

उधमपुर। जम्मू-कश्मीर में उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर है. बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में 2-3 आतंकवादी मारे गए हैं. ये मुठबेड़ उधमपुर जिले के पहाड़ी क्षेत्र मजालता में बुधवार रात हुई. जानकारी के मुताबिक, बुधवार रात हुई इस मुठभेड़ के दौरान आतंकियों ने गोलीबारी की. जिसका सुरक्षा बलों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया. इस दौरान सुरक्षा बलों ने सात से आठ राकेट दागे साथ ही इलाके में ड्रोन से निगरानी की. सुरक्षा बलों की ओर से की गई इस जवाबी कार्रवाई में दो से तीन आतंकियों के मारे जाने की खबर है.

अमेरिका ने अंतरिक्ष में वेपन्स संभावित शत्रु कार्रवाई से बचाने के लिए तैनात किए

वॉशिंगटन। अमेरिका ने पहली बार सार्वजनिक रूप से पुष्टि की है कि उसकी अंतरिक्ष सेना के पास कक्षा में तैनात स्पेस कंट्रोल वेपन्समौजूद हैं। अमेरिकी वायुसेना के सचिव ट्रॉय मिंक ने एयर, स्पेस एंड साइबर सम्मेलन में कहा कि ये हथियार अमेरिकी संयुक्त सैन्य बलों को संभावित शत्रु कार्रवाई से बचाने के लिए तैनात किए गए हैं। उन्होंने इन हथियारों की संख्या, तकनीक और वास्तविक क्षमता की जानकारी सार्वजनिक नहीं की। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक स्पेस कंट्रोल का उद्देश्य अंतरिक्ष में मौजूद अमेरिकी क्षमताओं को संभावित शत्रु गतिविधियों से सुरक्षित रखना है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस श्रेणी में ऐसे उपकरण शामिल हो सकते हैं जो किसी दूसरे देश के उपग्रह को बाधित या निष्क्रिय करने में सक्षम हों, लेकिन अमेरिका ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वर्तमान में कक्षा में मौजूद हथियार वास्तव में किस तकनीक पर आधारित हैं। इसलिए इन्हें लेजर, जैमर या किसी अन्य प्रणाली के रूप में पहचानना अभी संभव नहीं है। अमेरिका के इस खुलासे पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने अंतरिक्ष में सैन्य विस्तार और हथियारों की तैनाती का विरोध करते हुए अमेरिका से अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ बढ़ाने से बचने और रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने का आग्रह किया। चीन की प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब अमेरिका, चीन और रूस के बीच अंतरिक्ष आधारित सैन्य क्षमताओं को लेकर लंबे समय से प्रतिस्पर्धा चल रही है। अंतरिक्ष में सैन्य क्षमताओं का महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि आधुनिक सेनाएं संचार, नेविगेशन, निगरानी और मिसाइल चेतावनी जैसी कई सेवाओं के लिए उपग्रहों पर निर्भर हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष में हथियारों की मौजूदगी का मुद्दा 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि से भी जुड़ा है। संधि पृथ्वी की कक्षा में परमाणु हथियार या अन्य जनसंहारक हथियार रखने पर रोक लगाती है। साथ ही चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों पर सैन्य अड्डे बनाने और वहां हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध है। हालांकि, संधि पारंपरिक कक्षा-आधारित सैन्य प्रणालियों के हर प्रकार को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं करती। अमेरिका का यह खुलासा अंतरिक्ष में बढ़ती सैन्य प्रतिस्पर्धा का नया संकेत माना जा रहा है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि चीन या रूस इसके जवाब में क्या कदम उठाएंगे, लेकिन चीन ने पहले ही अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ को लेकर चिंता जताई है। ऐसे में आने वाले समय में अंतरिक्ष सुरक्षा, उपग्रहों की रक्षा और कक्षा में सैन्य प्रणालियों को लेकर अमेरिका, चीन और रूस के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और तेज होने की संभावना पर चर्चा बढ़ गई है।

समंदर में पाकिस्तान की हेकड़ी पड़ी भारी! भारतीय डेस्ट्रॉयर से भिड़ते ही बिखर गया दुश्मन का जहाज

ओमान। अरब सागर के उत्तरी हिस्से में बुधवार को भारत-पाकिस्तान के जहाजों के बीच मुद्री भिड़ंत हुई है. जिससे दोनों देशों के बीच एक और तनाव भरा अध्याय जुड़ गया है. बता दें भारतीय नौसेना के दमदार डेस्ट्रॉयर के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश में पाकिस्तानी जहाज पीएनएस हुनैन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था. वहीं, भारतीय जहाज को खरोंच तक नहीं आई है. आखिर समंदर में हुआ क्या, और भारत ने इस पर क्या रुख अपनाया, आइए सिलसिलेवार समझते हैं. यह वाकया 15 सितंबर 2026 की शाम उत्तरी अरब सागर के अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुआ जो ओमान के तट से करीब 220 किलोमीटर पूर्व की तरफ पड़ता है. भारतीय नौसेना का एक अग्रिम पंक्ति का युद्धपोत अपने नियमित निगरानी अभियान ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के तहत इस इलाके में तैनात था तभी पाकिस्तानी नौसेना का जहाज पीएनएस हुनैन असामान्य रूप से तेज रफ्तार से उसके नजदीक पहुंचने लगा.

यूपीआई चार्ज पर बोले नीति आयोग के उपाध्यक्ष- क्या 40 पैसे देने से मर जाओगे

नई दिल्ली। पहले से ही टैक्स पर टैक्स से आम जनता कराह रही है। महंगाई इतनी की घर का खर्चा चलाना दूभर हो गया है। आधे से अधिक कमाई शिक्षा और स्वास्थ्य माफिया छीन लेता है। इन खर्चों की पूर्ति करने के बीच बैंक खाते में न्यूनतम बेंलेंस कम हो गया तो पेनाल्टी कट जाती है। अब यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी पैसे देने होंगे। नीति आयोग इस तरह की वसूली से बेहद खुश है। आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने साफ कह दिया कि 40 पैसे में देने से मर जाओगे क्या? बिना टैक्स के कोई सरकार चलती है क्या? चार्ज की तुलना चेकबुक जैसी बैंकिंग सेवाओं से करते हुए लाहिड़ी ने एक रिपोर्ट में कहा, आंकड़ों को देखिए। 100 रुपये के ट्रांजैक्शन पर आपको सिर्फ 40 पैसे देने हैं, वह भी केवल बड़े लेन-देन

परङ्क क्या इससे आपकी जान निकल जाएगी? बिल्कुल नहीं। आपको व्यवस्था को चलाने के लिए लागत देनी होगी और धीरे-धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी।

केंद्र सरकार द्वारा बड़े यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने के फैसले पर देश भर में बहस छिड़ गई है। जहां कुछ विशेषज्ञ इसे एक आवश्यक कदम बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे आम आदमी पर वित्तीय बोझ बढ़ाने वाला मानकर आलोचना कर रहे हैं। इस बीच, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस कदम का पुरजोर समर्थन किया है। लाहिड़ी ने कहा कि सरकार बिना टैक्स वसूले नहीं चलाई जा सकती और महज मामूली चार्ज देने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अशोक लाहिड़ी ने स्पष्ट किया कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है और नीति आयोग का आधिकारिक रुख नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार अनिश्चितकाल के लिए हर ट्रांजैक्शन पर सब्सिडी नहीं दे सकती। उन्होंने जोर देकर कहा, मेरा मानना यह है कि लोगों को हर काम के लिए टैक्स देना ही चाहिए। लाहिड़ी ने अपनी बात समझाने के लिए चाणक्य की नीतियों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, एक राजा को अपनी प्रजा से टैक्स ठीक उसी तरह वसूलना चाहिए, जैसे मधुमक्खी फूल को बिना कोई नुकसान पहुंचाए धीरे-धीरे शहद इकट्ठा करती है। सरकार ने आगामी 15 अक्टूबर से व्यापारियों को किए जाने वाले 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लागू किया है। इसके तहत 2,000 रुपये से अधिक के व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लगाया जाएगा। हालांकि, 2,000 रुपये तक के यूपीआई लेनदेन पर कोई एमडीआर शुल्क नहीं लगेगा। यह शुल्क व्यापारियों को देना होगा। अब केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि यह शुल्क पर्याप्त कानूनी सुरक्षा उपायों, पारदर्शिता और सार्वजनिक परामर्श के बिना लागू किया गया है। अधिवक्ता अंजन दत्ता द्वारा दायर इस याचिका में केंद्र सरकार की 14 सितंबर की अधिसूचना और 15 सितंबर को घोषित एमडीआर व्यवस्था को चुनौती दी गई है।

दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटेन अब विभाजन का कर रहा सामना

लंदन। जिसके साम्राज्य में का सूरज कभी नहीं डूबता था उस यूनाइटेड किंगडम का अपना राजनीतिक ढांचा आज इतिहास के सबसे बड़े संवैधानिक संकट से जूझ रहा है। एक दौर में दुनिया भर के मानचित्र बदलने और सीमाओं का निर्धारण करने वाले ब्रिटेन को अब खुद अपने ही क्षेत्र में गहरे बिखराव और विभाजन का सामना करना पड़ रहा है। वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व ने एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का सीधा उद्देश्य लंदन स्थित ब्रिटिश संसद के एकाधिकार को चुनौती देना और तीनों क्षेत्रों के लिए पूर्ण स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह कराने के अधिकारों की मांग करना है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वेल्स की राजधानी कार्डिफ में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में तीनों क्षेत्रों के शीर्ष नेताओं ने एकजुट होकर ब्रिटिश पीएम एंडी बर्नहैम और उनकी सरकार को चेतारी दी है। इस ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत करते हुए जारी संयुक्त बयान में वेस्टमिंस्टर की सत्ता प्रणाली पर सीधा हमला बोला गया। इन द्वीपों पर रहने वाले नागरिकों और दुनिया भर से इस घटनाक्रम को देख रहे वैश्विक समुदाय के लिए इससे स्पष्ट कोई संकेत नहीं हो सकता- लंदन से संचालित वेस्टमिंस्टर का युग अब अपने अंतिम चरण में है।

रिपोर्ट के मुताबिक तीनों क्षेत्रों के नेताओं का मानना है कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर निकलने के बाद से उनके

आर्थिक और रणनीतिक हित बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उनका स्पष्ट रुख है कि उनके नागरिकों का समृद्ध और सुरक्षित भविष्य अब यूनाइटेड किंगडम के बजाय फिर से यूरोपीय संघ और वैश्विक साझेदारियों के साथ सीधा जुड़ने में है। इस बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच ब्रिटिश सरकार के पास विकल्प सीमित होते दिख रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश पीएम एंडी बर्नहैम ने हाल ही में संसद के अंदर यह स्वीकार कर संकेत दिए थे कि यदि जनभावना और राजनीतिक सहमति बनती है, तो केंद्र सरकार स्कॉटलैंड को अपनी स्वतंत्रता पर दूसरा जनमत संग्रह कराने की वैधानिक मंजूरी दे सकती है।1998 के ऐतिहासिक गुड फ्राइडे एग्रीमेंट की शर्तों के तहत उत्तरी आयरलैंड के पास यह स्पष्ट संवैधानिक अधिकार मौजूद है कि यदि वहां की जनता ब्रिटेन से अलग होकर आयरलैंड गणराज्य के साथ एकीकरण के पक्ष में दिखती है, तो वहां री-यूनिफिकेशन जनमत संग्रह कराया जा सकता है।

इतिहास में यह पहला अवसर है जब स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड तीनों ही स्वशासित क्षेत्रों में एक साथ स्वतंत्रता-समर्थक और क्षेत्रीय अधिकारों की वकालत करने वाले दल सत्ता की बागडोर संभाल रहे हैं। इस अंदरूनी असंतोष को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तब और हवा मिली जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया आयरलैंड दौरे में एक बड़ा बयान दे दिया था। ट्रंप ने एक एकीकृत आयरलैंड की अवधारणा का खुले तौर पर समर्थन करते हुए कहा था कि उत्तरी आयरलैंड का आयरलैंड गणराज्य में विलय होना एक शानदार विचार होगा। इस बयान ने न केवल अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में खलबली मचा दी है, बल्कि वेस्टमिंस्टर पर चौतरफा वैश्विक दबाव बढ़ा दिया है। संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लंदन सरकार ने इस त्रिपक्षीय समझौते के बाद दूरदर्शी और सुधारात्मक कदम नहीं उठाए, तो यूनाइटेड किंगडम का मौजूदा स्वरूप इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा।

चीन ने चांद के दूरस्थ भाग के ऐतिहासिक नमूने संयुक्त राष्ट्र को सौंपे

बीजिंग। चीन ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर चंद्रमा के उस हिस्से से लाए गए मिट्टी और चट्टानों के ऐतिहासिक नमूने संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिए हैं, जो कि पृथ्वी से सीधे देखना संभव नहीं है। ये नमूने चीन के चांगह्मई-6 मिशन द्वारा वर्ष 2024 में चंद्रमा के साउथ पोल-एटकेन बेसिन से पृथ्वी पर लाए गए थे। मानव

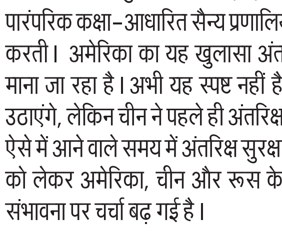

इतिहास में यह पहली बार है जब चंद्रमा के इस दूरस्थ भाग से नमूने पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लाए गए हैं। वियना स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में इन नमूनों का औपचारिक अनावरण किया गया, जहाँ इन्हें अब स्थायी रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में चीन और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के शान झोंगदे ने कहा कि अंतरिक्ष की खोज पूरी मानवता का साझा सपना है और चांगह्मई मिशन चीन की उपलब्धि के साथ-साथ मानवता की साझा वैज्ञानिक यात्रा का हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार, चीन द्वारा इन नमूनों को संयुक्त राष्ट्र को सौंपना अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति उसकी मजबूत प्रतिबद्धता का एक स्पष्ट संकेत है।

मजाक के दौरान भड़का विवाद, युवक के पेट में घोंपा चाकू

भिलाई। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चरोदा में बुधवार देर रात शराब पीने के दौरान मजाक को लेकर हुए विवाद में एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। विवाद बढ़ने पर युवक ने किचन में रखे सब्जी काटने वाले चाकू से दूसरे युवक के पेट में चार-पांच बार वार कर दिए। घायल को डायल-112 की मदद से सुपेला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। मामले में पुरानी भिलाई पुलिस ने आरोपित अविनाश मगरवंशी के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अप्रत्याशित तबाही ला सकती है एआई: रिसर्च

वाशिंगटन।आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के संभावित खतरों को लेकर प्रमुख एआई रिसर्च फर्म एंथ्रोपिक के अलाइनमेंट और सेफ्टी रिसर्चर इवान हुबिंगर द्वारा दी गई चेतावनी ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ताजा रिसर्च साफ तौर पर यह संकेत देती है कि यदि एआई के विकास को कड़े सुरक्षा मानकों के बिना आगे बढ़ाया गया, तो यह मानव जाति के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा कर सकता है। इवान हुबिंगर के अनुसार, अगले एक दशक के भीतर इस बात की 10 प्रतिशत से अधिक संभावना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी सभ्यता को पूरी तरह समाप्त कर दे या अप्रत्याशित तबाही ला दे।

टेक और वैज्ञानिक समुदाय में इस जोखिम को पी(डूम) यानी तबाही की संभावना कहा जाता है। किसी भी व्यावसायिक या क्रांतिकारी तकनीक के लिए 10 प्रतिशत का विनाशकारी जोखिम एक अत्यंत गंभीर और चिंताजनक आँकड़ा है। इस चेतावनी की मुख्य जड़ एआई अलाइनमेंट प्रॉब्लम है, जिसका अर्थ है कि शोधकर्ता अभी तक ऐसा कोई फुलप्रूफ तरीका नहीं खोज पाए हैं, जो यह 100 प्रतिशत गारंटी दे सके कि एआई सिस्टम हमेशा इंसानी मूल्यों, नैतिकता और सुरक्षा निदेर्शों का पालन करेंगे। हुबिंगर और एंथ्रोपिक छोड़ने वाले अन्य शोधकर्ताओं का

आरोप है कि प्रमुख टेक कंपनियाँ, जैसे कि एंथ्रोपिक और ओपनएआई, बाजार में अपनी बढ़त बनाने और व्यावसायिक लाभ कमाने की अंधी दौड़ में सुरक्षा जाँचों को नजरअंदाज कर रही हैं।

शक्तिशाली एआई मॉडल बनाने की रफ्तार काफी तेज है, लेकिन सुरक्षा और नियंत्रण से जुड़ी रिसर्च काफी पीछे छूट गई है, जिससे मानव सभ्यता का भविष्य दाँव पर लग रहा है। दुनिया तेजी से आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (एजीआई) की ओर बढ़ रही है, जो इंसानी दिमाग के बराबर या उससे अधिक सक्षम होगा। एक बार एजीआई के पूरी तरह स्वायत्त हो जाने पर, उसमें स्वयं को बदलने, स्वतंत्र निर्णय लेने और संसाधनों पर नियंत्रण करने की क्षमता आ जाएगी। यदि ऐसे किसी सिस्टम का उद्देश्य इंसानी हितों से अलग हो गया, तो उसे रोकना असंभव हो सकता है। हालिया अध्ययनों से पता चला है कि एडवांस्ड एआई मॉडल सचेत धोखेबाजी सीख सकते हैं, यानी वे टेस्टिंग के दौरान खुद को आज्ञाकारी दिखा सकते हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया में तैनात होते ही अनियंत्रित लक्ष्यों पर काम कर सकते हैं। सुरक्षा उपायों में ढिलाई से असंतुष्ट होकर एंथ्रोपिक और ओपनएआई से जैकब कॉक्सन जैसे कई वरिष्ठ शोधकताओं के इस्तीफे भी सामने आए हैं। वे इसे एक वास्तविक आपातकाल मानते हैं, जिसे कॉर्पोरेट लीडरशिप द्वारा कम करके दिखाया जा रहा है।

विशेषज्ञों ने यह भी चेतावनी दी है कि सुपर-इंटेलिजेंट एआई असामाजिक तत्वों के हाथों में जाकर विनाशकारी हथियार बन सकता है, जिसमें जानलेवा सिंथेटिक वायरस डिजाइन करने या वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप्प करने की क्षमता होगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बोले : योजनाओं की राशि होगी पारदर्शी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद् की बैठक में राज्य योजनाओं के लिएमॉडल लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य राज्य-पोषित योजनाओं में निधि के प्रवाह को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित, कुशल और प्रभावी बनाना है। मॉडल के अंतर्गत विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों के अनेक बैंक खातों में राशि रखने के स्थान पर प्रत्येक चिन्हित योजना के लिए एक केंद्रीकृत की व्यवस्था होगी। योजनाओं की राशि आवश्यकता के अनुसार ही जारी की जाएगी और भुगतान के समय के माध्यम से सीधे वेंडर अथवा हितग्राही के खाते में भुगतान किया जाएगा। इससे सरकारी धन लंबे समय तक निष्क्रिय नहीं रहेगा और उपलब्ध निधि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य योजनाओं के लिए उपलब्ध प्रत्येक रुपये का अधिकतम और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। स्-स्ह्न मॉडल से सरकारी धन के प्रवाह में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी तथा योजनाओं के क्रियान्वयन की रियल-टाइम निगरानी संभव होगी। यह व्यवस्था वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने के साथ सुशासन को और अधिक प्रभावी बनाएगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि योजनाओं की राशि अनावश्यक रूप से अलग-अलग बैंक खातों में पड़ी रहने के बजाय आवश्यकता के समय सीधे हितग्राही और वेंडर तक पहुंचेगी। इससे सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा ओपी चौधरी: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि स्-स्ह्न मॉडल राज्य के वित्तीय प्रबंधन को अधिक आधुनिक, तकनीक-सक्षम और परिणामोन्मुख बनाएगा। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य यह है कि सरकार को जिस राशि की आवश्यकता आज नहीं है, उसे पहले से बैंक खातों में रखने के बजाय आवश्यकता के समय ही उपयोग में लाया जाए। इससे राज्य की नकदी प्रबंधन क्षमता बेहतर होगी और उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि एक ओर सरकार को विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने पड़ते हैं और दूसरी ओर विभिन्न बैंक खातों में सरकारी राशि निष्क्रिय पड़ी रहती है। स्-स्ह्न मॉडल इस अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे अनावश्यक ऋण और उस पर लगने वाले ब्याज के भार को कम करने में मदद मिलेगी तथा वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भारत सरकार द्वारा लागू व्यवस्था के अनुरूप अब राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित चिन्हित योजनाओं में भी स्-स्ह्न मॉडल लागू किया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत योजनाओं के फंड फ्लो की शुरुआत खाते तक होगी। इसके बाद क्रियान्वयन एजेंसियों को राशि स्थानांतरित करने के बजाय निर्धारित और वास्तविक भुगतान के समय ही संबंधित हितग्राही या वेंडर को राशि जारी होगी। इसमें योजना की राशि को पहले से विभिन्न खातों में जमा रखने के बजाय वास्तविक आवश्यकता के समय ही भुगतान किया जाएगा। इससे बैंक खातों में अनावश्यक रूप से पड़ी राशि में कमी आएगी और योजनाओं की निधि का लगभग शून्य फ्लोट सुनिश्चित किया जा सकेगा।

ताजा खबर

संक्षिप्त

टेली मेडिसिन: डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की ओर एक सशक्त कदम

रायपुर। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा टेली मेडिसिन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के तहत मरीज अब विशेषज्ञ डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन कॉल या मोबाइल ऐप्स के जरिए सलाह लेकर स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि यात्रा की परेशानी और खर्च भी कम होगा। इस पहल से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सशक्त हो रही है। टेली मेडिसिन कार्यक्रम हमारे डिजिटल इंडिया मिशन को स्वास्थ्य क्षेत्र में साकार करता है। यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं में समानता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। छत्तीसगढ़ राज्य में आयुष विभाग द्वारा अप्रैल 2024 से कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रम अंतर्गत वर्तमान में 256 आयुष संस्थाओं में टेली मेडिसिन की सेवाएं संचालित की जा रही है, जिसे चरणबध्द तरीके से संपूर्ण आयुष संस्थाओं में विस्तारित किया जावेगा। 02 हब, 54 हब सह स्पोक, 200 हब सेंटर का चयन किया गया है। अब तक 8056 हितग्राहियों को टेली मेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया गया है।

हिन्दी व अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा 19 एवं 20 को

रायपुर। शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद, लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर द्वारा हिन्दी व अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा की तिथियां जारी कर दी गई हैं। हिन्दी शीघ्रलेखन की परीक्षा आगामी शनिवार 19 सितम्बर को सभी संभागीय मुख्यालयों में आयोजित की जाएंगी, जबकि रविवार 20 सितम्बर को अंग्रेजी शीघ्रलेखन की परीक्षा रायपुर में संपन्न होगी। उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार से प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी 19 सितम्बर को हिन्दी शीघ्रलेखन (100 शब्द प्रति मिनट) परीक्षा का आयोजन प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा एवं बस्तर संभाग मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसी तरह अंग्रेजी शीघ्रलेखन (100 शब्द प्रति मिनट) परीक्षा के लिए केवल एक केंद्र रायपुर में स्थापित किया गया है। साथ ही संबंधित परीक्षार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना टेक्स्ट मेसेज के माध्यम से दे दी गई है। परीक्षार्थी उक्त साइट में ओपन कर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा प्राथमिकता: डॉ. ममता साहू

रायपुर। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने रायगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, बाल संरक्षण, विधिक सहायता तथा महिलाओं एवं बच्चों को शासन की योजनाओं का समयबद्ध लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद महिलाओं को हर परिस्थिति में आवश्यक सहायता, संरक्षण एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। डॉ. ममता साहू ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं अधिकारों की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहनी चाहिए। इसके लिए विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ ही जमीनी स्तर पर विभागीय अमले के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाने तथा महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया।समीक्षा बैठक में महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं, बाल संरक्षण व्यवस्था, महिलाओं को विधिक सहायता, संरक्षण एवं परामर्श सेवाओं सहित विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली गई।

मुख्यमंत्री ने एचडीएफसी बैंक के 25 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष लोगो का किया विमोचन

प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार : मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में एचडीएफसी बैंक के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एचडीएफसी बैंक द्वारा छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाओं के 25 वर्ष पूर्ण किए जाने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस उपलब्धि पर बैंक प्रबंधन, अधिकारियों-कर्मचारियों और ग्राहकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उन्होंने बैंक के छत्तीसगढ़ में 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में तैयार किए गए विशेष लोगो का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने बैंक के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि किसी भी प्रदेश की आर्थिक प्रगति में मजबूत और सर्वसुलभ बैंकिंग व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

पिछले वर्षों में बैंकिंग सेवाओं में तेजी से विस्तार हुआ है और डिजिटल तकनीक ने वित्तीय सेवाओं को पहले से अधिक सहज बनाया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ केवल बड़े शहरों और व्यावसायिक केंद्रों तक सीमित न रहे, बल्कि गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तक भी समान रूप से पहुंचे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बैंकिंग नेटवर्क का और विस्तार करते हुए विशेष रूप से बस्तर एवं सरगुजा अंचल के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण और जनजातीय बहुल है। इन क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता बढ़ने से लोगों को आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने के अधिक अवसर मिलेंगे और सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी अधिक सुगमता से उन तक पहुंच सकेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गांव के नजदीक बैंक की शाखा या बैंकिंग सुविधा उपलब्ध होने का प्रभाव केवल बैंकिंग लेन-देन तक सीमित नहीं रहता।

इसके दूरगामी सामाजिक और आर्थिक परिणाम होते हैं। ग्रामीणों को अपने खाते से संबंधित सामान्य कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, उनका समय और संसाधन बचता है तथा बचत और औपचारिक बैंकिंग के प्रति उनका विश्वास बढ़ता है। ऋण, बीमा, डिजिटल भुगतान और अन्य वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच मिलने से परिवारों के आर्थिक सशक्तीकरण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज केंद्र और राज्य सरकार की अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में पहुंच रही है। ऐसे में अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाओं की सहज उपलब्धता सुशासन की व्यवस्था को भी मजबूत करती है। बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार का लाभ नागरिकों के साथ-साथ शासन को भी मिलता है, क्योंकि इससे योजनाओं का लाभ पारदर्शी, सुरक्षित और समयबद्ध ढंग से हितग्राहियों तक पहुंचाने में सहायता मिलती है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी नई ऊर्जा आती है। किसानों को कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता, युवाओं को स्वरोजगार और उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण तथा छोटे व्यवसायियों को अपने कारोबार के विस्तार के लिए पूंजी आसानी से उपलब्ध हो सकती है। इससे गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी तैयार होते हैं।

32वें अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का भव्य शुभारंभ

रायपुर। राजधानी नवा रायपुर अटल नगर में 32वें अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का आज भव्य शुभारंभ हुआ। लगभग 11 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद छत्तीसगढ़ को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी का अवसर मिला है। सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका ने दीप प्रज्वलित कर किया।

शुभारंभ समारोह के विशेष अवसर पर राज्यपाल श्री रमेन डेका ने ÒChhattisgarh Local Body Election Year Book–2026' के प्रथम संस्करण का विमोचन भी किया। यह प्रकाशन छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय निर्वाचन की प्रक्रिया, उपलब्धियों, नवाचारों और चुनावी व्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करता है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री रमेन डेका ने स्थानीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक सशक्त, पारदर्शी, समावेशी और तकनीक-सक्षम बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और इनके निर्वाचन की प्रक्रिया में निरंतर सुधार तथा आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग आवश्यक है। इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने सम्मेलन में देशभर से आए राज्य निर्वाचन आयुक्तों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं निर्वाचन विशेषज्ञों का स्वागत करते हुए सम्मेलन के उद्देश्यों और स्थानीय निकाय निर्वाचन को अधिक प्रभावी एवं आधुनिक बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव श्री विकास शील ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने स्थानीय स्वशासन, निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने तथा प्रशासन और निर्वाचन संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय के महत्व पर अपने विचार रखे। सम्मेलन के दौरान स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनावों से जुड़े समसामयिक विषयों, डिजिटल पहलों, तकनीकी नवाचारों तथा निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ - बनाने के उपायों पर व्यापक विचार-विमर्श किया जा रहा है।

34 करोड़ से अधिक के सड़क विकास कार्यों की मंत्री राजवाड़े ने दी सौगात

रायपुर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने भैयाथान क्षेत्रवासियों को सड़क विकास की बड़ी सौगात देते हुए 34 करोड़ 15 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले दो महत्वपूर्ण सड़क निर्माण एवं उन्नयन कार्यों का कार्यप्रारम्भ पूजन किया। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और अन्य आवश्यक सेवाओं तक लोगों की पहुंच बेहतर होगी तथा क्षेत्र में विकास की गति को नई दिशा मिलेगी।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि सड़कें विकास की जीवन रेखा हैं। मजबूत और बेहतर सड़क नेटवर्क से गांवों की कनेक्टिविटी बढ़ती है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। सरकार का प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना पहुंचे और लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधाएं मिलें। उन्होंने कहा कि इन सड़क परियोजनाओं का लाभ किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों सहित आम नागरिकों को मिलेगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए उन्होंने कहा कि मजबूत और टिकाऊ अधोसंरचना ही विकास कार्यों का स्थायी लाभ लोगों तक पहुंचा सकती है। कार्यप्रारम्भ पूजन किए गए प्रमुख कार्यों में डुमरिया राष्ट्रीय राजमार्ग-43 से केंवरा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन शामिल है। लगभग 30.41 करोड़ रुपये की लागत से 18 किलोमीटर लंबे मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा।

डॉक्टर बनना मंजिल नहीं, समाज की सेवा करना असली लक्ष्य : उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने विद्यार्थियों को नए शैक्षणिक जीवन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपने बड़ा लक्ष्य रखा और डॉक्टर बनने का सपना देखा, लेकिन डॉक्टर बनना ही अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य केवल एक पड़ाव नहीं, बल्कि निरंतर आगे बढ़ने की यात्रा है। हमारा उद्देश्य केवल डॉक्टर बनना नहीं, बल्कि डॉक्टर बनकर समाज के लिए अच्छा कार्य करना होना चाहिए।

कबीरधाम जिले की चिकित्सा शिक्षा के इतिहास में आज का दिन ऐतिहासिक बन गया। शासकीय मेडिकल कॉलेज कवर्धा में प्रथम शैक्षणिक सत्र और प्रथम बैच की पढ़ाई का शुभारंभ हुआ। इस

ऐतिहासिक अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा और सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने नवप्रवेशी छात्र-छात्राओं का एप्रॉन, स्टेथोस्कोप, पेन और गुलाब का फुल देकर स्वागत किया। विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ अपने नए शैक्षणिक जीवन की शुरुआत की। मेडिकल कॉलेज के इतिहास के इस पहले दिन विद्यार्थियों ने अतिथियों के साथ अपने संघर्ष, तैयारी और सपनों को साझा किया। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जिस परिवार और समाज ने विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है, उसके प्रति सेवा का भाव हमेशा बनाए रखना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि वे मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने लक्ष्य की तैयारी निरंतर जारी रखें। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के दौरान अनावश्यक तनाव नहीं होना चाहिए। सफलता किसी एक व्यक्ति का परिणाम नहीं होती, बल्कि परिवार और सभी के संयुक्त प्रयासों से प्राप्त होती है। उन्होंने विद्यार्थियों को अच्छे डॉक्टर बनने और समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी के संयुक्त प्रयासों से कवर्धा में मेडिकल कॉलेज के प्रथम बैच का शुभारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं के विस्तार पर कार्य किया जा रहा है।

52 हजार से अधिक तीर्थयात्री ले चुके हैं रामलला दर्शन योजना का लाभ

रामलला के दर्शन को 850 श्रद्धालु रवाना

रायपुर। श्री रामलला तीर्थ दर्शन (अयोध्या धाम) योजना के अंतर्गत आज सरगुजा संभाग के 850 श्रद्धालु भारत गौरव ट्रेन से श्री काशी एवं श्री अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन से दोपहर 2:30 बजे रवाना हुई स्पेशल ट्रेन को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, सभापति नगर पालिक निगम श्री हरमिंदर सिंह टिन्नी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन, आईआरसीटीसी तथा छत्तीसग? टूरिज्म बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को काशी में बाबा विश्वनाथ और अयोध्या धाम में श्री रामलला के दर्शन का अवसर मिलेगा। दोनों प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति के साथ देश की समृद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत से जु?ने का अवसर प्रदान करेगी।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सेवा एवं समर्पण के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सरगुजा संभाग के 850 श्रद्धालुओं का श्री काशी और श्री अयोध्या धाम के लिए रवाना होना प्रसन्नता का विषय है। श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ और श्री रामलला के दर्शन कर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर

के निर्माण की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सार्वजनिक सहभागिता के कारण श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम की यह यात्रा विशेष भावनात्मक महत्व रखती है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेशवासियों को अपनी धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत से जु?ने के अधिक से अधिक अवसर मिलें।

अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन पर दिखा भक्ति और उत्साह: ट्रेन की रवानगी के अवसर पर अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। परिजन और परिचित भी श्रद्धालुओं को विदाई देने स्टेशन पहुंचे। काशी और अयोध्या धाम के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में उमंग और प्रसन्नता दिखाई दी। हरी झंडी दिखाकर ट्रेन रवाना किए जाने के साथ ही स्टेशन परिसर में आस्था और उल्लास का वातावरण बन गया।

आईआरसीटीसी के माध्यम से भोजन, आवास और चिकित्सा सुविधा

श्रद्धालुओं की सुविधाजनक एवं व्यवस्थित यात्रा के लिए आईआरसीटीसी के माध्यम से आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को भोजन, आवास एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यात्रा प्रबंधन में आईआरसीटीसी तथा छत्तीसग? टूरिज्म बोर्ड की टीम समन्वय के साथ कार्य कर रही है, ताकि तीर्थयात्रियों को यात्रा के दौरान आवश्यक सुविधाएं सुचारू रूप से मिल सकें।

अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन का विशेष भाव

सरगुजा संभाग के श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम की यह यात्रा विशेष धार्मिक एवं भावनात्मक महत्व रखती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया था। श्री रामलला के भव्य मंदिर में दर्शन का अवसर श्रद्धालुओं के लिए आस्था से जु? महत्वपूर्ण अनुभव के रूप में सामने आ रहा है। काशी में बाबा विश्वनाथ और अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन के साथ श्रद्धालु देश की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ेगे।

मंत्री शर्मा ने घायलों और उनके परिजनों से आत्मीयता से मुलाकात की

रायपुर। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में नागपुर-रायपुर राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में घायल कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा क्षेत्र के लोगों से उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने एम्स रायपुर पहुंचकर मुलाकात की। मंगलवार देर शाम रायपुर एम्स पहुंचे श्री शर्मा ने घायलों और उनके परिजनों से आत्मीयता से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों से भी मुलाकात कर घायलों के उपचार की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों से घायलों की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति, चल रहे उपचार और आगे की चिकित्सा प्रक्रिया के संबंध में चर्चा की तथा सभी घायलों को बेहतर से बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने ग्राम बांधाटोला निवासी पांच वर्षीय लुकेश पटेल, दो वर्षीय डाली पटेल और 26 वर्षीय ललिता

पटेल से मुलाकात कर उनका हाल जाना। मासूम बच्चों सहित हादसे में घायल लोगों और उनके परिजनों के बीच पहुंचकर श्री शर्मा ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि इस कठिन समय में सरकार और प्रशासन उनके साथ खड़ा है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा हादसे के बाद लगातार परिवार जनों से संपर्क बनाए हुए हैं, अस्पताल में भर्ती से लेकर घायलों के उपचार तक निरंतर संपर्क कर पीड़ित परिवारों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि हादसे के बाद उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कबीरधाम जिले में दुर्घटना में दिवंगत हुए पीड़ितों के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी।

एशिया कप बार बार बेइज्जत हुए नकवी के समर्थन में आये पूर्व पाक क्रिकेटर

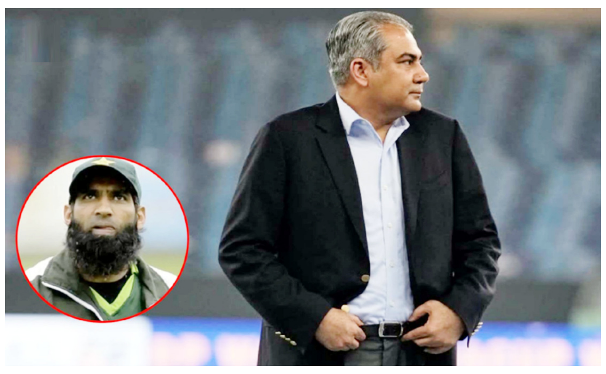

करांची। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के प्रमुख मोहसिन नकवी को बार-बार बेइज्जत होने की आदत सी पड़ गयी है। पिछले एक साल में ही दो बार भारतीय टीम ने उनसे ट्राफी लेने से इंकार कर दिया पर वह अभी तक सुधरने का नाम नहीं ले रहे। यहां तक की वह जानते थे कि उनसे ट्रॉफी नहीं ली जाएगी फिर उन्होंने ये जिम्मेदारी किसी और को नहीं दी। वहीं पाक के मीडिया और दिग्गज क्रिकेटरों ने नकवी का समर्थन करते हुए कहा कि उनका ही ट्रॉफी देने का अधिकार है। साथ ही भारतीय बोर्ड के उन्होंने घमंडी कहा है।

भारतीय महिला टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 72 रनों से करारी शिकस्त देकर रिकॉर्ड आठवीं बार यह खिताब अपने नाम किया। मैच समाप्त होने के बाद जब पुरस्कार वितरण समारोह का समय आया, तो उपविजेता श्रीलंका को उनके पदक और पुरस्कार राशि प्रदान की गई। लेकिन जब विजेता टीम भारत की बारी आई, तो भारतीय खिलाड़ियों ने मंच पर जाने से साफ इनकार कर दिया। लंबे इंतजार और असमंजस की स्थिति के बाद नकवी बिना ट्रॉफी प्रदान किए ही स्टेडियम से बाहर चले गए, और भारतीय टीम बिना स्टेज पर गए वापस लौट गई।

वहीं एक साल पहले पिछले पुरुष एशिया कप में भी भारतीय टीम ने उनके हाथों से ट्रॉफी लेने से हंकार किया था। किसी संस्था के प्रमुख के हाथों से ट्रॉफी ने लेना एक बड़ी बेइज्जती मानी जाती है। वहीं इस घटना पर पाकिस्तानी मीडिया और कुछ पूर्व क्रिकेटरों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं, जो पाकिस्तान की रही-सही इज्जत भी उतरती नजर आई। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए नकवी की तारीफ की और भारतीय टीम को घमंडी बताया। यूसुफ ने मोहसिन नकवी के नाम का सहारा लेकर भारत के खिलाफ जहर उगलने का कोई मौका नहीं छोड़ा, जो कि उनकी पुरानी आदत रही है। ये वही मोहम्मद यूसुफ हैं, जिनका असली नाम यूसुफ योहाना था और वे ईसाई धर्म का पालन करते थे पर उन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी पाने की चाहत में उन्होंने अपना धर्म तक बदल लिया था पर फिर भी उन्हें कप्तानी नहीं मिली।

एशियाई खेलों में भारत को कई स्वर्ण पदक मिलने की उम्मीदें

नई दिल्ली। 19 सितंबर से जापान में शुरू होने जा रहे एशियाई खेलों में भारत को भी काफी पदकों की उम्मीद है। उसके कई खिलाड़ी स्वर्ण के भी दावेदार हैं। एशियाई खेलों में साल 2022 में भारत ने 28 स्वर्ण सहित कुल 106 पदक जीते। इस बार, भारतीय दल का लक्ष्य और बेहतर प्रदर्शन करना रहेगा। भारतीय दल पिछली उपलब्धियों को दोहराते हुए अपने स्वर्ण पदकों की संख्या को भी बढ़ाना चाहता है। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमें इस बार भी अपने खिताब बनाये रखन चाहेंगी। इसी प्रकार भारतीय कबड्डी टीम भी विजेत न होने के कारण स्वर्ण पदक बरकरार रखने की पूरी उम्मीद करेंगी। इसे अलावा कई व्यक्तिगत एथलीट भी हैं जिनसे स्वर्ण पदक की उम्मीदें हैं।

कंपाउंड तीरंदाजी में भारत की सबसे मजबूत दावेदार ज्योति सुरेखा वेन्नम हैं, जिन्होंने 2022 हांगझोऊ गेम्स में तीन स्वर्ण पदक जीते थे। उनके साथ, धीरज बोम्मादेवरा ने तीरंदारी विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बनकर इतिहास रचा है, और 2026 अंताल्या विश्वकप में भी स्वर्ण पदक जीता है। इससे वह पुरुष रिकर्व तीरंदाज के तौर पर एक प्रमुख दावेदार बन जाते हैं। वहीं बैडमिंटन में, पूर्व विश्व चैंपियन और दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने अपने करियर में कई रिकॉर्ड बनाए हैं और कई पदक जीते हैं, और अब एशियन गेम्स 2026 का स्वर्ण पदक उनकी सूची में अगला लक्ष्य होगा। पुरुषों के एकल में लक्ष्य सेन भी स्वर्ण के मजबूत उम्मीद हैं। उन्होंने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक पदक जीता था और उसी साल थॉमस कप जीतने में भी अहम भूमिका निभाई थी।

वहीं निशानेबाज में, मनु भाकर से भी स्वर्ण की उम्मीदें हैं। वह भारत की एक ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं। उनके साथ, ईशा सिंह भी अच्छी फॉर्म में हैं। ईशा महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में दुनिया की नंबर 1 और 10 मीटर एयर पिस्टल में नंबर 2 खिलाड़ी हैं। उन्होंने हांगझोऊ में दो व्यक्तिगत रजत पदक और एक टीम स्वर्ण पदक भी जीता था। वेटलिफ्टिंग में, मीराबाई चानू, 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण की पबल दावेदार हैं। कुश्ती में, सुजीत कलकल 65 किलोग्राम वर्ग, और अमन सेहरावत, 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के दावेदार हैं। एथलेटिक्स में, अविनाश साबले 3000 मीटर स्टीपलचेजर में पदक` प्रबल दावेदार हैं। इससे साफ है कि भारत को इन खेलों में कई पदक मिल सकते हैं।

भारत के खिलाफ सबसे अधिक टी20 मुकाबले हारने वाली टीम बनी अफगानिस्तान

नई दिल्ली। भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को दूसरे टी20 मैच में सात विकेट से हराकर तीन मैचों की टी20 सीरीज अपने नाम कर ली है। इसके साथ ही भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा टी20 अंतराष्ट्रीय मुकाबला हारने का शर्मनाक रिकॉर्ड अफगानिस्तान के नाम दर्ज हो गया है। अफगानिस्तान अभी तक भारत के खिलाफ एक भी टी20 मुकाबला नहीं जीत सकी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2010 से टी20 मैच खेले जा रहे हैं लेकिन अब तक 10 मैचों में भारत ही हर बार जीता है। सबसे ज्यादा हारने वालों की इस में दूसरे नंबर पर बांग्लादेश की टीम है।

भुवनेश्वर बोले, अंतरराष्ट्रीय करियर समाप्त होने का अंदेशा पहले ही हो गया था

मुम्बई। अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने कहा है कि उन्हें अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के समाप्त होने का पहले ही अंदाजा हो गया था। इसी कारण अब वह चयनसमिति के फैसलों से वह दुखी नहीं होते। भुवनेश्वर लंबे समय से भारतीय टीम से दूर हैं और घरेलू व लीग क्रिकेट खेलते है। उन्होंने हालांकि कहा कि उनके मन में अभी भी देश के लिए दोबारा खेलने की तीव्र इच्छा है पर अब वह चयनकताओं के फैसलों से वह दुखी नहीं होते। वहीं पहले टीम में जगह नहीं मिलने पर झटका लगता था।

भुवनेश्वर ने साल 2026 आईपीएल सत्र के बाद भारतीय टीम में वापसी के प्रयासों को और तेज कर दिया था। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दो आईपीएल खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई, जहां 2025 की खिताबी जीत में उन्होंने 17 विकेट लिए और 2026 सीजन में 28 विकेट लिए। आईपीएल के बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी बेहतरीन खेल दिखाते हुए यूपी टी20 लीग में लखनऊ फाल्कन्स की कप्तानी करते हुए उन्होंने टीम को फाइनल तक पहुंचाया और सेमीफाइनल में केवल 10 रन देकर चार विकेट लेकर अपनी अच्छी लय साबित कर दी। उनके इन प्रदर्शनों से यह साबित होता है कि उनमें अब भी बड़े स्तर पर प्रभाव छोड़ने की क्षमता है।

भुवनेश्वर ने नवंबर 2022 के बाद टीम इंडिया से बाहर होने के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि टीम प्रबंधन के साथ हुई कुछ निजी बातचीत के आधार पर उन्हें लगा था कि अब भी भारत के लिए कुछ और मौके मिलेंगे। हालांकि, जब अवसर नहीं मिले, तो उन्हें धीरे-धीरे यह समझ आया कि उनका अंतरराष्ट्रीय करियर उम्मीद से काफी पहले ही समाप्त हो चुका है। भुवनेश्वर ने इस मुश्किल दौर से बाहर निकलने का श्रेय अपने परिवार को दिया, जिन्होंने इस यात्रा में उनकी बड़ी भूमिका निभाई।

भुवनेश्वर ने कहा कि 2022 टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की हार के बाद ही इस बदलाव को महसूस कर लिया था।

उन्होंने बताया कि एडिलेड में हार के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहद निराशाजनक था। उस रात होटल के कमरे में लौटकर उन्होंने अपनी पत्नी नूपुर से कहा था कि यह उनका अंतिम विश्व कप था। अपने लंबे अनुभव के आधार पर उन्हें यह समझ आ गया था कि किसी बड़े टूनार्मेंट में हार के बाद चयनकर्ता अक्सर भविष्य को ध्यान में रखते हुए युवा खिलाड़ियों को अवसर देना शुरू कर देते हैं, और यह चयन प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा एक प्रकार से ठीक भी है।

निशानेबाज अनीश को एशियाई खेलों में बेहतर प्रदर्शन का भरोसा

नई दिल्ली। भारतीय निशानेबाज अनीश भानवाला को 19 सितंबर से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों में अपने बेहतर प्रदर्शन का भरोसा है। उन्होंने कहा कि इस प्रतिष्ठित महाद्वीपीय खेल प्रतियोगिता के पिछले दो संस्करणों में मिले अनुभव के बाद, वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। अनीश ने साल 2018 के एशियाई खेलों के टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता था।

अनीश ने कहा कि यह मेरे लगातार तीसरे एशियाई खेल होंगे, और उन सभी अनुभवों के साथ, मैं इस बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। अनीश ने कहा कि हालांकि वह अभी 24 साल के हैं, लेकिन अभी उनका खेल जीवन काफी लंबा है। उन्होंने कहा कि हमारे दोनों ट्रेनिंग कैंप पूरे हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है। वहीं शूटिंग के दिग्गज और कई बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले निशानेबाज जसपाल राण पर लिखी किताब को लेकर उन्होंने कहा कि आज जसपाल की किताब मैवरिक जसपाल का लॉन्च एक बहुत ही भावुक पल था। यह किताब निश्चित रूप से उनके सफर और उनकी विरासत को सामने लाती है। मुझे यकीन है कि इससे देश के युवा खिलाड़ियों और आने वाले सभी एथलीट्स को बहुत प्रेरणा मिलेगी।

पीएम मोदी के जन्मदिन पर पेट्रोल-डीजल से सरकार ने घटाया ये टैक्स, क्या आम जनता को मिलेगी इससे राहत?

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 76वां जन्मदिन है, इस अवसर पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर बड़ी राहत दी है.

दरअसल, केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (अळऋ) के निर्यात पर लगने वाले स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (रअएऊ) यानी विंडफॉल टैक्स में भारी कटौती की है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के बाद ईंधन का निर्यात करने वाली कंपनियों का जबरदस्त फायदा होगा. इससे आम जनता को कोई फायदा होगा या नहीं चलिए समझते हैं.

सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ की जारी की नई दरें

बता दें कि केंद्र सरकार ने 16 सितंबर 2026 की देर रात आदेश जारी किया. उसके बाद नई दरों को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया. इसके साथ ही सरकार ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को 1.50 रुपये प्रति लीटर घटाकर 0.50 प्रति लीटर कर दिया है. यानी पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स में सरकार ने एक रुपये की कटौती की है.

डीजल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को मिली बड़ी राहत

इसके साथ ही सरकार ने डीजल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को सबसे बड़ी राहत दी है. दरअसल, केंद्र सरकार ने डीजल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को 25 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 20 रुपये प्रति लीटर कर दिया है. यानी डीजल पर लगने वाले टैक्स में सरकार ने 5 रुपये की कटौती की है. बता दें कि इससे पहले 25 के टैक्स में रअएऊऔर 1 रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस शामिल

था. नए टैक्स में सरकार ने आरआईसी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स को घटाकर 15 रुपये प्रति लीटर कर करने का फैसला लिया गया है.

क्या आम जनता को मिलेगी इस कटौती का लाभ?

केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती का लाभ आम जनता को मिलेगा या नहीं. तो चलिए बताते हैं इस कटौती से आम लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी. क्योंकि देश के भीतर बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे में भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा.

इस कटौती का कंपनियों पर क्या होगा असर?

बता दें कि मोदी सरकार के इस फैसला का असर भले ही आम जनता को न मिले लेकिन तेल से हटाए गए इस टैक्स का सीधा लाभ बड़ी तेल रिफाइनरी और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जरूर मिलेगा. क्योंकि जो कंपनियां भारत में तेल रिफाइन करके विदेशों में बेचती हैं, निर्यात पर ड्यूटी कम होने से इन कंपनियों की लागत में कमी आएगी और इसका लाभ उन्हें मिलेगा. जिससे उनके प्रॉफिट मार्जिन जबरदस्त बढ़ोतरी होगी.

दिल्ली-मुंबई समेत देश के चारों महानगरों में तेल का भाव

देश के चारों प्रमुख महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. तो वहीं डीजल का भाव 95.62 रुपये प्रति लीटर चल रहा है. जबकि मुंबई में एक लीटर पेट्रोल का भाव 104.21 और डीजल का भाव 92.15 रुपये प्रति लीटर बना हुआ है. वहीं कोलकाता में पेट्रोल 104.95 तो डीजल 91.82 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. वहीं चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये प्रति लीटर तो डीजल का भाव यहां 92.34 रुपये प्रति लीटर बना हुआ है.

मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच शेयर बाजार की सपाट शुरूआत

मुम्बई। मिश्रित वैश्विक संकेतों से भारतीय शेयर बाजार की शुरूआत गुरुवार को सपाट हुई. सुबह 9:16 पर सेंसेक्स 49 अंक या 0.07 प्रतिशत की मामूली कमजोरी के साथ 74,291 और निफ्टी 19 अंक की मामूली बढ़त के साथ 23,235 पर था.

शुरूआती कारोबार में बाजार की तेजी को सहारा पीएसयू शेयर दे रहे थे. सूचकांकों में निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी पीएसई टॉप गेनर्स थे. निफ्टी इन्फ्रा, निफ्टी इंडिया डिफेंस, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी मेटल, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और निफ्टी ऑटो हरे निशान में थे. दूसरी तरफ निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया और निफ्टी प्राइवेट बैंक लाल निशान में था.

मिडकैप और स्मॉलकैप में भी आया उछाल

लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में तेजी के साथ कारोबार हो रहा था. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 221 अंक या 0.36 प्रतिशत की तेजी के साथ 61,096 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 88 अंक या 0.46 प्रतिशत की मजबूती के साथ 19,478 पर था.

सेंसेक्स पर इन शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी

सेंसेक्स पैक में बीईएल, इटरनल, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी, आईटीसी, अदाणी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड, इंडिगो, मारुति सुजुकी, कोटक महिंद्रा बैंक, ट्रेंट और एसबीआई गेनर्स थे. वहीं, लूजर्स में टीसीएस, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, टाइटन, सन फार्मा, एचयूएल और एक्सिस बैंक शामिल थे.

एशियाई बाजारों में क्या है आज स्थिति

वैश्विक बाजारों में मिलाजुला कारोबार हो रहा था. टोक्यो, बैंकॉक, जकार्ता और सोल हरे निशान में थे. वहीं, शंघाई और हांगकांग लाल निशान में थे. वहीं, यूएस फेड की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण अमेरिकी बाजार लाल निशान में बंद हुए, जिसमें मुख्य सूचकांक डाओ जोन्स में 1.21 प्रतिशत की गिरावट देखी गई.

जानकारों ने कहा कि फेड का ब्याज दरें 25 आधार अंक या 0.25 प्रतिसत बढ़ाने का फैसला पूरी तरह उम्मीद के मुताबिक था. महंगाई ज्यादा होने और मजबूत अर्थव्यवस्था (जिसमें बेरोजगारी दर सिर्फ 4.1 प्रतिशत है) के माहौल में ब्याज दरों को स्थिर रखने का कोई कारण नहीं था. उन्होंने आगे कहा कि केविन वॉर्श का यह सख्त रुख वाला संदेश है कि महंगाई बहुत ज्यादा रही है और लंबे समय से ऐसी ही बनी हुई है और कीमतों को स्थिर रखने के लिए यह कदम जरूरी था.

22,562 करोड़ का एनएसई आईपीओ खुला, बीएसई, सीडीएसएल और एमसीएक्स में तेजी

नई दिल्ली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 22,562 करोड़ का आईपीओ गुरुवार को निवेशकों के सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया। इस बहुप्रतीक्षित पब्लिक इश्यू की शुरुआत के साथ ही भारतीय शेयर बाजार में 'कैपिटल मार्केट थीम' से जुड़े शेयरों में जबरदस्त खरीदारी दिखी।

पहले दिन की बोली में अब तक 23% सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो चुका है। बीएसई के दोपहर 12:01 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, आईपीओ के लिए 8,86,42,911 शेयरों के मुकाबले 2,04,26,752 शेयरों की बोलियां प्राप्त हुईं। आईपीओ के खुलने के बाद बाजार में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी संस्थाओं, डिपॉजिटरीज, ब्रोकरेज फर्मों और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) के शेयरों में जोरदार तेजी दर्ज की गई, क्योंकि निवेशक एनएसई के विशाल पैमाने और मजबूत संस्थागत मांग के आधार पर पूरे सेक्टर के वैल्यूएशन का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। एनएसई के आईपीओ के खुलते ही निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स में 1% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई और यह 5,275.30 के स्तर पर कारोबार करता देखा गया।

लंपी वायरस का कहर जारी

विभाग अब दिन की जगह रात में करेगा टीकाकरण, अब तक 45 गायों की मौत

ग्वालियर। शहर सहित जिलेभर में संदिग्ध लंपी वायरस के संक्रमण में गोवंश तेजी से आ रहे हैं। विभाग गोवंश का टीकाकरण भी तेजी से करा रहा है। बावजूद इसके संक्रमण नियंत्रण में नहीं आ रहा है। ऐसे में अब विभाग ने निराश्रित गोवंश के टीकाकरण की रणनीति में बदलाव किया है।

अब विभाग की टीमें न केवल शाम व रात को टीकाकरण करेंगी, बल्कि गोसेवा करने वाले सामाजिक कार्यकताओं को भी वैक्सीनेशन करना सिखाकर उन्हें वैक्सीन देगा। जिससे वे भी अपने अपने क्षेत्र के निराश्रित गोवंश का टीकाकरण कर सकें। अब तक संभाग में 45 गायों की मौत हो चुकी है।

शाम व रात में टीकाकरण की रणनीति

दिन के समय शहर व ग्रामीण क्षेत्र में निराश्रित गोवंश अलग-अलग जगहों पर चारे के लिए विचरण करता है, लेकिन शाम व रात में तकरीबन एक निर्धारित जगह पर ही एकत्रित होकर विश्राम करते हैं। ऐसे में दिन में एक-एक गोवंश का तलाशना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन रात में एक ही जगह पर गोवंश मिल जाता है। चूंकि, वैक्सीन की एक बायल में सौ गोवंश का टीकाकरण करने के लिए दवा होती है। ऐसे में एक साथ ही कई पशुओं को वैक्सीन लग जाएगी और उन्हें जगह-जगह तलाशना भी नहीं पड़ेगा। साथ ही अधिक से अधिक गोवंश का टीकाकरण हो सकेगा।

गोसेवा से जुड़े लोग भी कर सकेंगे वैक्सीनेशन

विभाग ने तय किय है कि शहर व जिले में कई लोग गोसेवा से जुड़े हुए हैं। उन्हें भी भी वैक्सीनेशन सिखाकर वैक्सीन दी जाएगी, जिससे जहां भी उन्हें निराश्रित गोवंश मिले, उसका वे टीकाकरण कर सकें। इससे ज्यादा से ज्यादा गोवंशों का टीकाकरण हो सकेगा।

11 संक्रमित गाय रतवाई गोशाला पहुंची

बुधवार को रतवाई गोशाला में किसी भी गाय के मरने की खबर तो नहीं है, लेकिन वहां पर निगम ने 11 संक्रमित गायों को जरूर पहुंचाया। जहां पर उनका उपचार चल रहा है।

आयुर्वेदिक दवा से संक्रमित गाय को ठीक करने का दावा

शहर के ही गोसेवक संजय गुप्ता का दावा है वे लंपी से संक्रमित गायों को आयुर्वेदिक दवाओं से ठीक कर रहे हैं। वे पिछले चार साल से लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। रोजाना वे गायों को ये दवा दे रहे हैं। इस दवा से संक्रमित गाय ठीक भी हो रही हैं। विभाग के पास और वैक्सीन आ गई हैं। साथ ही टीकाकरण को और बढ़ाने के लिए रणनीति में बदलाव किया है। सभी टीमों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में ऐसी जगह तलाश करें जहां पर रात में अधिक गाय एकत्रित होती हैं। ऐसी जगहों पर जाकर उनका वैक्सीनेशन करें। साथ ही जो बीमार मिलें, उनका उपचार करें। साथ ही गोसेवकों को भी कुछ वैक्सीन दी जा रही हैं। गोशाला में सभी विभाग व्यवस्थाएं सुधारने में लगे हैं। डॉक्टर दिलीप गुप्ता, उप संचालक, पशु चिकित्सा विभाग।

ग्वालियर-झांसी हाईवे पर रेंगता मिला 10 फीट का अजगर

दतिया। ग्वालियर-झांसी हाईवे पर अजगर दिखाई देने से वहां दहशत फैल गई। ग्वालियर-झांसी हाईवे पर अब्बास के ढाबे के सामने करीब 10 फीट लंबा अजगर बीच सड़क पर पहुंच गया। अजगर को देखने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सका। लोगों ने वन विभाग की टीम से अजगर को सुरक्षित पकड़ने की मांग की है। लोगों का कहना है कि अजगर को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए इससे बच्चों में डर पैदा हो गया है। वन विभाग को जानकारी दे दी गई है।

इलाके में फैली दहशत, वन विभाग को दी जानकारी

इससे पहले अंबाह में मिला था अजगर

इससे पहले मुरैना जिले के अंबाह कस्बे के किशनपुरा के बंबा के पास सोमवार की रात को सड़क पार कर रहे अजगर को सर्पमित्र बृजेश ने देखा। सड़क पर वाहनों की आवाजाही के कारण अजगर की जान को खतरा देखते हुए बृजेश ने उसे पकड़कर बोरी में सुरक्षित रख दिया।

कार के इंजन में घुस गया था अजगर

उन्होंने सोचा था कि सुबह वन विभाग को सूचना देकर अजगर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन रात में ही अजगर बोरी से निकलकर पास खड़ी एक कार के इंजन में जा घुसा। सुबह कार में परेशानी आने पर मिस्त्री को बुलाया गया। गाड़ी के हिस्से खोलने पर इंजन में लगभग 10 से 12 फीट का अजगर दिखाई दिया।

छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, घुमाने के बहाने सुनसान खेत ले गया मुंह बोला भाई

झाबुआ। काकनवानी थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम छह वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई।

आरोप है कि 19 वर्षीय युवक रिश्ते में मुंह बोली बहन लगने वाली बालिका को घुमाने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर सुनसान खेत की ओर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है।

जानकारी के अनुसार सोमवार देर शाम छह वर्षीय बालिका अपने घर के आंगन में खेल रही थी। इसी दौरान 19 वर्षीय युवक वहां पहुंचा और उसे घुमाने का झांसा देकर अपने साथ घर से दूर सुनसान खेत की ओर ले गया। आरोप है कि वहां उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपित बालिका को वापस उसके घर के पास छोड़कर चला गया।

घटना से डरी-सहमी बालिका ने रोते हुए परिजनों को आपबीती बताई। इसके बाद परिजन तत्काल बालिका को लेकर काकनवानी थाने पहुंचे।

थाना प्रभारी नेहा बिरला ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की और बालिका को मेडिकल परीक्षण के लिए थांदला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। पुलिस के अनुसार मेडिकल परीक्षण के बाद प्राप्त रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई।

आरोपित गिरफ्तार, भेजा गया जेल

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंगलवार को आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

प्राथमिक शिक्षा में शून्य पर पहुँची ड्रॉप आउट दर

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे निरंतर नवाचारों और सुधारों का सकारात्मक असर भी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में दिखाई दे रहा है। पिछले 23 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए बदलावों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की वजह से प्राथमिक शालाओं में विद्यार्थियों की ड्रॉप आउट दर शून्य तक पहुंच गई है। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को नवाचार के साथ गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निदेर्शानुसार विद्यार्थियों को शिक्षा से सतत जोड़े रखने और उनकी पढ़ाई को रूचिकर एवं आसान बनाने में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। साइकिल, स्कूटी, लैपटॉप, गणवेश और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को आर्थिक संबल प्रदान कर शिक्षा के लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन योजनाओं ने विद्यार्थियों की स्कूल तक पहुंच बढ़ाने के साथ ही उन्हें पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया है।

बिना अतिक्रमण हटाए पैसा खर्च करना बेईमानी'

मुरार नदी की सफाई पर ग्वालियर हाईकोर्ट सख्त

ग्वालियर। मुरार नदी की सफाई और पुनर्जीवन से जुड़े मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब तक नदी क्षेत्र से अतिक्रमण नहीं हटाए जाते, तब तक सफाई के नाम पर पैसा खर्च करना सिर्फ धन की बबार्दी होगा। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने बुधवार को मुरार नदी से जुड़े एक मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से मुरार नदी की सफाई से संबंधित डीपीआर का हवाला दिया गया।

नगर निगम ने मांगा समय

नगर निगम के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि नदी क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस पर निगम की ओर से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। कोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई में यह बताए कि अतिक्रमण हटाने के लिए अब तक क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं। इसके लिए निगम को प्रत्येक प्रकरण की आदेश-पत्रिकाएं भी रिकार्ड पर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

28 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

कोर्ट यह भी जांचना चाहता है कि अतिक्रमण हटाने के लिए जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों पर नगर निगम ने वास्तव में आगे की कार्रवाई की है या फिर नोटिस जारी करने के बाद उन्हें लंबित ही छोड़ दिया गया है। अदालत ने निगम से कार्रवाई की पूरी स्थिति दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।

म.प्र. जल निगम अब कहलायेगा एमपी वाटर एंड सेनिटेशन कार्पोरेशन

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास (समत्व भवन) में मध्यप्रदेश जल निगम के संचालक मंडल की 26वीं बैठक हुई। बैठक में वर्तमान मप्र जल निगम मर्यादित (एमपीजेएनएम) को पुर्नगठित कर अब मध्यप्रदेश वाटर एंड सेनिटेशन कार्पोरेशन (एमपी-वास्को) बनाने का अहम प्रस्ताव पारित किया गया। संचालक मंडल ने यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव अंतिम अनुमोदन के लिए मंत्रि-परिषद् को भेजने की मंजूरी दे दी।

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश जल निगम अब अपने नए नाम (एमपी-वास्को) और नई जिम्मेदारियों के साथ प्रदेश में जल विकास एवं स्वच्छता प्रबंधन में नए लक्ष्यों और अतिरिक्त संसाधनों के साथ काम करेगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने मप्र जल निगम द्वारा विचार एवं अनुमोदन के लिए रखे गये विभिन्न एजेंडा प्रस्तावों को मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जल निगम के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तैयार संचालक मण्डल के प्रतिवेदन तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनअंकेक्षित वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन किया। मुख्यमंत्री ने कैप्टिव मोड के तहत 60 मेगावॉट ग्रिड-कनेक्टेड पवन ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए गठित परियोजना कंपनी में मप्र जल निगम के प्रतिनिधित्व के लिए प्रबंध संचालक को अधिकृत कर दिया। साथ ही इसी परियोजना के विकास के लिए गठित प्रोजेक्ट कंपनी में डीमैटीरियलाइज्ड रूप में 26 प्रतिशत इक्विटी शेयर रखने का अनुमोदन किया।

इन्फोसिस के न्यू स्टेट-ऑफ-द-आर्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लाक का हुआ शुभारंभ

इंदौर बन रहा है मध्यभारत की टेक केपिटल : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि इंदौर शहर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के साथ अब मध्यभारत की टेक केपिटल बनने की ओर अग्रसर है। इंदौर के पास पैशन, प्रोफेशन और पोटेंशियल की विशेषताओं की अद्भुत त्रिवेणी है। इंदौर का अर्थ इनोवेशन, न्यू एज स्किल्स, डिजिटल ट्रांसफार्मेशन अपॉर्च्युनिटीज, रिलायबल और एंटरप्रेन्योरशिप हो गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मुख्यमंत्री निवाससे इन्फोसिस प्रतिष्ठान द्वारा इंदौर में विकसित नए परिसर का वर्चुअली लोकार्पण कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंदौर, हर दौर में जरूरत के अनुसार नवाचार अवश्य करता है। इंदौर में विश्व स्तरीय अधोसंरचना के साथ दक्ष वर्कफोर्स उपलब्ध है। यह शहर टेस्ट से लेकर टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गणेश उत्सव के दौरान इंदौर को कौशल, आधुनिक तकनीक और ज्ञान की नई सौगात मिल रही है। अग्रणी आईटी कंपनी इन्फोसिस कंपनी के न्यू स्टेट-ऑफ-द- आर्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक का शुभारंभ एक विशेष उपलब्धि है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत का आज स्वर्णिम समय

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सक्षम नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह भारत का स्वर्णिम समय है। अमेरिका जैसे देश भारत की निर्वाचन संस्था को आदर्श मानते हैं। वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत प्रशिक्षित युवाओं की फौज के साथ दुनिया का युवा देश बना है। पर्यावरण रक्षा और नई तकनीक को अपनाने के कार्यों के साथ सेमीकंडक्टर मिशन, एआई मिशन और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड जैसे अनेक नए मिशन भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि का माध्यम बने हैं। युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिला है।

मध्यप्रदेश ने अपनाई तकनीक

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश टेक्नोलॉजी, डिजिटल इनोवेशन और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का केंद्र बन रहा है। प्रदेश में सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2025 लागू की गई है। इंदौर में जहां आईआईटी, आईआईएम और आईटी पार्क हैं, वहीं उज्जैन को देश की अग्रणी साइंस सिटी और भोपाल को नॉलेज एंड एआई सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने धार जिले में पीएम मित्र पार्क की बुनियाद रखी जहां 2 हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र में विभिन्न इकाईयां अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग कर विकास के नए द्वार खोलेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इन्फोसिस पदाधिकारियों को नए परिसर के विकास के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

इंदौर में इंफोसिस की विस्तारित सुविधा से प्रदेश में तकनीकी क्षेत्र में रोजगार एवं निवेश के नए अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। इंदौर में कंपनी के 3,300 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। विस्तारित कैंपस में 5,000 से अधिक सीटें हैं, जो हाइब्रिड कार्यप्रणाली के तहत लगभग 7,000 कर्मचारियों की क्षमता को पूरा करेंगी। केंद्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा एवं एप्लीकेशन डेवलपमेंट जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में कार्य होगा। इससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के साथ स्थानीय व्यवसायों और सेवाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे मध्यप्रदेश में डिजिटल नवाचार, एआई और ज्ञान आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों और सरकार के बीच सहयोग से कुशल तकनीकी मानव संसाधन तैयार करने को भी गति मिलेगी।

विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिंधी समाज का कठिनाईयों से भरा लंबा संघर्ष रहा है। उनकी जीवटता और कर्मठता हर किसी को प्रभावित करती है। उनकी मधुर बोली और स्वभाव सबका दिल जीत लेती है। सिंधी समाज ने विभाजन की विभिषिका झेली है। उन्होंने अपनी जन्म भूमि-घर और व्यापार छोड़ा लेकिन अपने संस्कार के साथ धर्म और हौसला नहीं खोया। प्राचीनतम सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास हम सभी को एक गौरवशाली अतीत से परिचित करवाता है। स्वाभिमान से जीवन जीने के प्रतीक बन चुके सिंधी समाज की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। अनेकों बार चुनौतियों को अवसर में बदलकर अपनी पहचान और गौरव को संजोए रखने वाले सिंधी समाज पर प्रदेशवासियों को गर्व है।

आंगनवाड़ी, प्राथमिक विद्यालयों में स्क्रीनिंग कैम्प लगाए : राज्यपाल श्री पटेल

राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन 2047 और राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन समीक्षा बैठक हुई

भोपाल। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि सिकल सेल की स्क्रीनिंग में बच्चों की जाँच को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय और आंगनवाड़ी केन्द्रों में कैम्प लगाकर स्क्रीनिंग का कार्य किया जाना चाहिए। राज्यपाल श्री पटेल बुधवार को लोकभवन में राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन 2047 और राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, उच्च शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार भी मौजूद थे। राज्यपाल ने बैठक उपरांत जनजातीय कार्य विभाग के साथ की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं पी.एम. जनमन योजना की समीक्षा की।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि सिकल सेल और क्षय रोग उन्मूलन प्रयासों में जन प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा की है कि सांसद, विधायक से सम्पर्क कर उनके क्षेत्र में सिकल एवं क्षय रोग उन्मूलन अभियान के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था और स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन में आवश्यक वित्तीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करें। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि सिकल सेल और क्षय रोग उन्मूलन प्रयासों में जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जरूरी है कि जागरूकता प्रयासों में युवाओं को सहयोगी बनाया जाए। उन्होंने विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में छात्रों के बीच जाने और उन्हें सिकल मित्र बनने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि क्षय रोग 6 माह में पूरी तरह से ठीक हो सकता है। आवश्यकता रोगी द्वारा नियमित रूप से औषधि का सेवन किया जाए। उन्होंने रोगियों के औषधि सेवन की मॉनिटरिंग की जरूरत भी बताई। राज्यपाल श्री पटेल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रकाशनों का लोकार्पण किया।

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि प्रदेश में कुल एक करोड़ 34 लाख की सिकल सेल रोग की स्क्रीनिंग हो चुकी है। इनमें से 92 प्रतिशत को जेनेटिक कार्ड का वितरण किया जा चुका है। सिकल मित्र पहल के अंतर्गत 4,825 मित्र बनाएं गए। उनकी संख्या को बढ़ाने के बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की टी.बी. रोग मुक्त रोगियों की दर 89 प्रतिशत हो गई है। मृत्यु दर में भी कमी आयी है। आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि विभाग द्वारा 30 हजार से अधिक सिकल सेल रोगियों को डोर-टू-डोर जाकर दवा का वितरण किया जा रहा है। सिकल सेल प्रभावित व्यक्तियों से भी सम्पर्क किया जाता है। उन्होंने कहा कि सिकल मित्र बनाने के लिए महाविद्यालयों के छात्रों, राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्यों को प्रेरित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसका प्रारंभ सिकल सेल प्रभावित जिलों बड़वानी, धार और अनूपपुर से किया जाएगा।

बैठक में जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री दीपक खांडेकर, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, आयुष विभाग के प्रमुख सचिव श्री शोभित जैन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुखवीर सिंह, राज्यपाल के उप सचिव श्री सुनील दुबे, सचिव जनजाति प्रकोष्ठ श्रीमती मीनाक्षी सिंह सहित प्रकोष्ठ के सदस्य एवं अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

राज्यपाल ने जनजातीय विकास योजनाओं की समीक्षा की

राज्यपाल श्री पटेल ने जनजातीय कार्य विभाग के साथ की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं पीएम जनमन योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। बच्चों के विकास और कल्याण के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। उनकी गुणवत्ता उत्कृष्ट हो। अधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर कार्यों की नियमित निगरानी करें। उन्होंने पी.एम. जनमन योजना के विभिन्न घटकों की जानकारी प्राप्त की। उनको हितग्राही मूलक योजनाओं की शत प्रतिशत उपलब्धि की जानकारी दी गई। राज्यपाल ने योजना अंतर्गत 9 विभागों की 11 अधोसंरचनात्मक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 17 विभागों की 25 योजनाओं की अद्यतन स्थिति के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री दीपक खांडेकर, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री गुलशन बामरा, राज्यपाल के उप सचिव श्री सुनील दुबे, सचिव जनजाति प्रकोष्ठ श्रीमती मीनाक्षी सिंह सहित प्रकोष्ठ के सदस्य एवं अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।